सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh
RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 125, नई दिल्ली । मंगलवार, 16 जुलाई 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

हिसाब किताब सिर्फ ऊपर वाले ने ही सही लगाया, सबको खाली हाथ भेजा और खाली हाथ बुलाया

03 मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन
06 ऐतिहासिक नए बजट की उम्मीद
08 परीक्षा में सुरक्षा की कमजोर कड़ियां

परिवहन विशेष हिन्दी दैनिक राष्ट्रीय समाचार पत्र नवम्बर माह में मोटर वाहन नियम/अधिनियम एवं सड़क सुरक्षा के प्रति

1. प्रदर्शनी,
2. संगोष्ठी,
3. विशेषज्ञ विचार एवम्
4. सड़क सुरक्षा पर आधारित पुस्तक लोकार्पण समारोह आयोजित करने जा रहा है।

इस पत्रिका में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत सरकार एवम् उच्च न्यायालय (सभी राज्य भारत सरकार) द्वारा जनहित में जारी गैजेट नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन, आदेशों, दिशा निर्देशों को एक साथ उपल्ब्ध करवाएंगे और साथ ही यह विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे की किस राज्य के परिवहन विभाग द्वारा इनमें से क्या लागू है और क्या नहीं।

*जनहित और जन जागरूकता के प्रति समर्पित ट्रांसपोर्ट टुडे के इस विशेष अंक में जानकार, ज्ञानविध विशेषज्ञों से सहयोग प्रदान करने के लिए निवेदन करते हैं।

"आपके पास मोटर वाहन नियम अधिनियम और सड़क सुरक्षा से सम्बंधित जो जानकारी है उसे हमे जन जागरूकता के प्रति उपल्ब्ध करवाए"

हम पत्रिका में आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी को आपके नाम से प्रस्तुत करेंगे।

जन जागरूकता में इस उद्देश्य को सफल बनवाने में सहयोग प्रदान करने वालो को योगदान के प्रति सम्मान समारोह में सम्मानित किया जाएगा।

आज भारत देश में हम सब का दायित्व बनता है की अगर सड़क सुरक्षा के प्रति हम सक्षम है, जानकार है तो अपनें ज्ञान के माध्यम से सड़क दुर्घटना जीरो कराने के प्रति जागरूकता फैलाने में सहयोग करे।

आशा करता हू हमारे द्वारा करे जाने वाले इस प्रयास में आप अपना पूर्ण योगदान प्रदान कर राज्य परिवहन विभागो एवम् अन्य विभागों द्वारा की जा रही कमियों को दूर करवाने और भारत देश में सड़क दुर्घटना के साथ सड़को पर होने वाली जान माल क्षति को रोकने के हिस्सेदार बनेंगे।

संजय बाटला
संपादक, परिवहन विशेष हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

परिवहन विशेष
देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक हिन्दी समाचार पत्र
RNI Number:- DELHIN/2023/86499

बाटला जी, सडक सुरक्षा को लेकर आपका प्रयास और अभियान सराहनीय पहल है ।इसके लिए हम हमेशा तैयार है ।बहरहाल, वर्तमान में बढ रहे सडक हादसौ के कारणों पर एक श्वेत पत्र लाने की जरूरत है। दरअसल सडक हादसौ को रोकने के लिए बनी एजेंसिया ही बडा कारण है। जो चंद पैसों की खातिर वह सब होने देती जो होना नहीं चाहिए। ट्रैफिक पुलिस कानून के नाम पर उगाही में जुटी रहती है। इलाकई पुलिस भी गैरजिम्मेदाराना रूख दिखाते हुए अनदेखा करती है। इसकी जद में सब पैसो का खेल है ।मुख्य सडको के दोनो ओर पुलिस और क्षेत्रीय नेताओ की शह पर अवैध सडकों पर कब्जा हो चुका है। दुकानदारों द्वारा फुटपाथ की जगह सामान को रखा जा चुका है। आखिर पैदल राहगीर, जिसमें बच्चे ,बूढ़े, विक्लांग, महिलाए तक बीच ट्रेफिक के चलने को मजबूर है ।राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश में ये ही हालत है। इससे साबित होता है कि सडक सुरक्षा में लगी सरकारी एजेंसियां,ही जनहानि के लिए जिम्मेदार है। मेरे विचार से आम नागरिक को जागरूक करने से पहले सरकारी गैरजिम्मेदार ऐजेंसियो जिनमें ट्रैफिक पुलिस,क्षेत्रीय पुलिस को उनकी ड्यूटी के प्रति जागरूक करने की जरूरत है। जब नियम बनाने वाले ही तोडक दस्ते में शामिल हो तो तमाम जागरूकता अभियान धाराशाही हो जाएगे ।आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस समय कई स्वंय सेवी संस्थाए,समाजिक संस्थाए सडक सुरक्षा को लेकर बडे-बडे प्रचारित बोर्ड लगाकर अपना नाम दिखाने की जुगत में लगी है। बावजूद इसके उनके तमाम सड़क सुरक्षा अभियान, और प्रचार प्रसार के इरादे जमीन पर धाराशाही हो रहे हैं। इसकी वजह सरकारी ऐजेंसियों की रिश्वतखोरी, उगाही के बल पर धड्डले से चल रहे उनके और आकाओ के धंधे है । चौराहे की लाइटे महीनों-महीनों खराब पडी रहती है। जेब्रा क्रासिंग का पेंट मिट चुका है ।लेकिन उनको दुरूस्त करवाने की बजाए, पेडों की आढ में छिपकर कथित रक्षक ही नियम तोडने वालो के शिकार करने में लगे है। सडकों के किनारे ट्रैफिक पुलिस की हफ्ता चौथ पर अवैध पार्किंग चल रही है। सडक के दोनों और अवैध गाडी पार्किंग,दूसरी ओर फुटपाथ पर एंकरोचमैंट से सडक सुरक्षा की उम्मीद कैसे लगा सकते है ।उदाहरण के तौर पर दिल्ली के अवंतिका रोहिणी रेड लाइट से जयपुर गोल्डन अस्पताल तक की सडक के दोनो तरफ अवैध कारोबार पार्किंग हो रही है। यहां मोटर डीलर्स की दुकाने लाइन से है। 5₹5 फिट की छोटी-छोटी दुकाने खोल कर बाहर सडक पर सैंकडो गाडियों को पार्क कर रखा है। वैसे आम आदमी की कार अगर सडक किनारे खडी है तो ट्रैफिक पुलिस की क्रेन तुरंत टॉचन कर उठा लेते है। लेकिन यहां ट्रैफिक पुलिस का कार डीलर्स से महीना बंधा हुआ है। यहां लाइन से इन अवैध कार पार्किंग की वजह से सडक संकरी हो गई है। 40-50 फिट चौडी सडक सिर्फ 10-12 फिट में तब्दील हो चुकी है। ऐसे में महज आम निरीह जनता को ही जागरूक करने से ट्रैफिक जाम की समस्या खत्म तो नहीं होने वाली है। बता दें की सडको पर अवैध कब्जा करने की कार्रवाई में सरकारी एजेंसियां ही शामिल है। लिहाजा सडक सुरक्षा का पाठ इन्ही सरकारी ऐजेंसियो,जिनमें ट्रैफिक पुलिस, और लोकल पुलिस ही जागरूक हो जाए तो सडक सुरक्षातंत्र में आमूलचूल परिवर्तन दिखाई देगा। सडको पर बसों के चलने के लिए पीली लाइन खींच तो दी है लेकिन ये पीली पट्टी कहीं पर दिखाई नहीं दे रही है? सब जगह अवैध कब्जा और वसूली का खेल चल रहा है। बहरहाल परिवहन विशेष के माध्यम से हम अपनी ओर से पहल करके देख लेते हैं,हो सकता है कि इस सडी-गली उगाही व्यवस्था में कुछ सुधार की गुंजाइश या रोशनी की किरण दिखाई दे।

एसडी सेठी, रोहिणी दिल्ली

दिल्ली में 'मोहल्ला बस' का ट्रायल रन शुरू

परिवहन विशेष न्यूज

सुषमा रानी, नई दिल्ली। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में लास्ट-माईल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक उठाते हुए आज से मोहल्ला बस सेवाओं का ट्रायल शुरू किया है ।आज से शुरू होने वाला ट्रायल 7 दिनों तक चलेगा और वर्तमान में दो मार्गों पर संचालित होगा। ये मार्ग हैं: प्रधान एन्क्लेव पुस्ता से मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन और अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन से मयूर विहार फ़ेज-III पेपर मार्केट तक।

परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, ₹मोहल्ला बस सेवाओं की शुरूआत दिल्ली में लास्ट माईल कनेक्टिविटी को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन बसों को सीमित सड़क चौड़ाई और उच्च भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में नेविगेट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस ट्रायल के द्वारा हम यात्रियों से उनके अनुभव के आधार पर आवश्यक फीडबैक इकट्ठा कर रहे हैं जिससे मोहल्ला बसों की सेवा का विस्तार दिल्ली के सभी इलाक़ों में लास्ट माईल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने हेतु किया जाएगा।"

मोहल्ला बस 196 किलोवाट की कुल क्षमता वाले छह बैटरी पैक से सुसज्जित है, जो 45 मिनट की चार्जिंग के साथ 200+ किमी की रेंज प्रदान करती है ।9 मीटर की इन मोहल्ला बसों में 23 यात्री सीटें और 13 यात्रियों के खड़े होने की क्षमता है।

आसानी से पहचान के लिए मोहल्ला बसों को हरे रंग का रखा गया है। मोहल्ला बसों में 25% सीटें (6 सीटें) गुलाबी रंग की हैं, जो विशेष रूप से महिला यात्रियों के लिए आरक्षित हैं।

मोहल्ला बस योजना का लक्ष्य 9 मीटर लंबी इलेक्ट्रिक बसों के द्वारा दिल्लीवासियों को उनके घर के आसपास फीडर बस सेवाएं प्रदान करना है ।केजरीवाल सरकार की योजना 2025 तक कुल 2,180 ऐसी बसें शुरू करने की है, जो विशेष रूप से सीमित सड़क चौड़ाई या भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों के लिए होंगी। दिल्ली सरकार वर्तमान में लास्ट माईल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) से अधिग्रहित 100 बसों का संचालन कर रही है ।इन मोहल्ला बसों की अधिकतम रूट लंबाई 10 किमी है। दिल्ली सरकार द्वारा कुल 2,080 9-मीटर बसें खरीदी जा रही हैं। इसमें डीटीसी की 1,040 बसें और डिम्ट्स की 1,040 बसें शामिल हैं ।ये बसें खासकर उन क्षेत्रों में जहां मानक 12 मीटर बसें अपने आकार और मोड़ त्रिज्या के कारण परिचालन चुनौतियों का सामना करती हैं, वहाँ परिचालित की जा सकेंगी।

मोहल्ला बसों में किराया दिल्ली सरकार की एसी बसों के समान ही होगा, यानी ₹10, ₹15, ₹20 और ₹25। महिलाएं पिंक पास के जरिए इन बसों में मुफ्त यात्रा का लाभ उठा सकती हैं।

ट्रायल रूट 1: मजलिस पार्क से प्रधान एन्क्लेव

प्रधान एन्क्लेव पुस्ता (लिटिल स्टार स्कूल), प्रधान एन्क्लेव ए-ब्लॉक, बाबा कॉलोनी पुस्ता ,एपेक्स स्कूल ,जगतपुर मोड़ ,मिलन विहार चौक ,झोरडा पुलिस चौकी (कायाकल्प अस्पताल),संगम विहार गली नंबर-4, झारोदा मेट्रो स्टेशन ,हरदेव नगर, बुराड़ी मेट्रो स्टेशन ,बुराड़ी क्रॉसिंग ,मुकुंदपुर चौराहा, मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन

ट्रायल रूट 2: अक्षरधाम से मयूर विहार फेज-III, अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन ,दिल्ली पुलिस अपार्टमेंट ,नोएडा मोड़,मयूर विहार फेज-1 मेट्रो स्टेशन ,मयूर विहार फेज-1 एसटीए अथॉरिटी, मेट्रो स्टेशन पॉकेट-ए गुरुद्वारा,त्रिलोक पुरी-36 ब्लॉक, त्रिलोक पुरी-26 ब्लॉक ,त्रिलोक पुरी-13 ब्लॉक, चाँद सिनेमा, सुपर बाज़ार, कल्याण पुरी चौराहा ,कोंडली मोड़,राजबीर कॉलोनी पुल नंबर-1,बड़ी मस्जिद पुल नंबर-2, ग़ाज़ीपुर थाना, घरोली एक्सटेंशन, सपेरा बस्ती, मयूर विहार फेज-III पेपर मार्केट

केजरीवाल सरकार ने मोहल्ला बसों की पार्किंग और रखरखाव के लिए पूरी दिल्ली में 16 डिपो बनाए हैं।

मोहल्ला बसों के लिए डिपो

पूर्वी ज़ोन गाजीपुर डिपो में 60मोहल्ला बसें होंगी,ईस्ट विनोद नगर में 180 मोहल्ला बसें होंगी।

पश्चिम ज़ोन

द्वारका मुख्य डिपो में 40 मोहल्ला बसें होंगी,द्वारका सेक्टर 2 डिपो में 180 मोहल्ला बसें होंगी ,केशोपुर डिपो 180 मोहल्ला बसों को समायोजित करेगा ,पीरागढ़ी डिपो में 135 मोहल्ला बसें होंगी,शादीपुर डिपो में 230 मोहल्ला बसें होंगी, द्वारका सेक्टर 9 डिपो में 20 मोहल्ला बसें होंगी।

दक्षिण ज़ोन कुशक नाला डिपो में 350 मोहल्ला बसें होंगी ।अंबेडकर नगर डिपो में 180 मोहल्ला बसें होंगी।

उत्तरी ज़ोन मुंडका डिपो में 60 मोहल्ला बसें होंगी,नांगलोई डीएमआरसी में 60 मोहल्ला बसें होंगी,नांगलोई डीटीसी डिपो में 180 मोहल्ला बसें होंगी,रिठाला डिपो में 70 मोहल्ला बसें होंगी,कोहाट एन्क्लेव डिपो में 35 मोहल्ला बसें होंगी। नरेला बस डिपो में 180 मोहल्ला बसें होंगी।

मोहल्ला बस योजना दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन और लास्ट माईल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, खासकर उन इलाकों में जहां बड़ी बसों को परिचालन संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

जल्द ही हाईवे पर टोल प्लाजा पर बैरियर के उठने का इंतजार किए बिना निकल सकेंगे, लागू होगी यह नई व्यवस्था

ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम पर आधारित बैरियर-फ्री टोल कलेक्शन की शुरुआत के साथ, हाईवे पर गाड़ी चलाने वाले यूजर्स को बिना किसी असुविधा के टोल गेट से 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक की तेज रफ्तार से जाने की अनुमति दी जाएगी।

ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS) पर आधारित बैरियर-फ्री टोल कलेक्शन की शुरुआत के साथ, हाईवे पर गाड़ी चलाने वाले यूजर्स को बिना किसी असुविधा के टोल गेट से 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक की तेज रफ्तार से जाने की अनुमति दी जाएगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है।

वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हाईवे यूजर फीस क्लेक्शन व्यवस्था का विकल्प चुनने वाले वाहनों के लिए शुल्क प्लाजा पर शुरुआत में एक या दो लेन उपलब्ध होंगी। उन्होंने बताया कि यह व्यवस्था जल्द ही शुरू की जाने वाली है। अधिकारी ने कहा, ₹सरकार को उम्मीद है कि इससे टोल कलेक्शन में लीकेज को रोकने और टोल डिफॉल्टरों की जांच करने में मदद मिलेगी। लेन अग्रिम रीडिंग, पहचान और प्रवर्तन उपकरणों से लैस होंगी ताकि सिर्फ वैध वाहन ही गेट से गुजर सकें।"

GNSS-आधारित टोल कलेक्शन सिस्टम के तहत, हाईवे पर तय की गई दूरी के आधार पर टोल लिया जाता है। वहीं मौजूदा तरीके के तहत, भले ही यूजर टोल रोड के एक हिस्से की यात्रा करता है, उसे एक निश्चित राशि का भुगतान करना पड़ता है। सैटेलाइट-आधारित सिस्टम वाहन की गतिविधि को ट्रैक करती है और वाहनों में लगे ऑन बोर्ड यूनिट की मदद से शुल्क की गणना करती है।

पहले इन वाहनों पर होगा लागू

पहले चरण में, जीएनएसएस-आधारित टोलिंग को वाणिज्यिक वाहनों के लिए लागू करने का प्रस्ताव है। और बाद में निजी वाहनों को शामिल किया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने हाल ही में GNSS-आधारित टोल संग्रह को विकसित और कार्यान्वित करने के लिए अभिनव और योग्य कंपनियों से वैश्विक निविदा आमंत्रित की है। अधिसूचना के अनुसार, इच्छुक कंपनियां भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रवर्तित एक फर्म, भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड को अवगत करा सकती हैं। जिसने निविदा आमंत्रित की है।

चुनी जाने वाली एजेंसी मौजूदा प्लाजा के भीतर डेडिकेटेड जीएनएसएस लेन के लेआउट को विकसित करेगी। जिसमें अग्रिम साइनेज, मार्किंग, लाइटिंग और उपकरणों की नियुक्ति शामिल है। ताकि जीएनएसएस से लैस वाहनों को टोल प्लाजा से गुजरने वाले धीमी रफ्तार वाले रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन-आधारित (फास्टैग) वाहनों के साथ संघर्ष किए बिना सुविधा हो सके।

अधिकारियों ने बताया कि हाई परफॉर्मेंस वाले उपकरण ऑटोमैटिक नंबर प्लेट पहचान कैमरों के जरिए वाहन पंजीकरण संख्या पढ़ते हैं, वाहन की पहचान करते हैं। और वाहन के एक्सेल और टाइप के आधार पर वजन का अनुमान लगाते हैं, और टोल शुल्क लेते हैं।

शुरुआत में, एक हाइब्रिड मॉडल, जिसमें RFID-आधारित फास्टैग और GNSS-सक्षम टोल संग्रह दोनों शामिल हैं। प्रस्तावित व्यवस्था को सुचारू रूप से अपनाए जाने तक दोनों व्यवस्था एक साथ चलेगी। अधिकारियों ने बताया कि टोल प्लाजा पर सभी लेन आखिरकार जीएनएसएस लेन में बदल दी जाएंगी।

एनएचएआई को लगभग 70,000 किलोमीटर लंबाई के नेशनल हाईवे के रखरखाव और प्रबंधन का काम सौंपा गया है। जो कुल 1,50,000 किलोमीटर नेटवर्क का हिस्सा है।

इसके अलावा, नेशनल हाईवे फीस (दरों का निर्धारण और संग्रह) नियम, 2008 के अनुसार इन हाईवे पर यूजर फीस वसूलने का दायित्व एनएचएआई को सौंपा गया है। इस समय, नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे के लगभग 45,000 किलोमीटर के लिए टोल वसूला जाता है।

टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)
TOLWA
website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com
रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल - 0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण
रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

किस तरह होती है दिल्ली मेट्रो की सफाई, कैसे हमेशा चमकती रहती है मेट्रो

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली मेट्रो की सर्विस पिछले 22 सालों से चल रही है और रोजाना लाखों लोग सफर करते हैं. अगर आप दिल्ली मेट्रो की सर्विस से संतुष्ट नहीं हैं तो इसे बेहतर बनाने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को सुझाव दे सकते हैं. दिल्ली मेट्रो के 10वें ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण की शुरुआत आज (15 जुलाई) से हो रही है और ये 14 अगस्त तक चलेगा. ये सर्वे मुख्य रूप से मेट्रो सेवाओं और सुविधाओं पर आधारित होगा. दिल्ली मेट्रो यात्रियों के लिए लाइफलाइन बन चुकी है और हमेशा बेहतर सुविधा के लिए जानी जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिल्ली मेट्रो की सफाई कैसे होती है और ट्रेनों के अलावा स्टेशन कैसे हमेशा चमकते रहते हैं.

रोजाना 60 लाख लोग करते हैं सफर

दिसंबर 2002 में शुरू हुई दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) में हर दिन एवरेज 60 लाख से ज्यादा लोग ट्रैवल करते हैं. 13 फरवरी 2024 को दिल्ली मेट्रो से 71.09 लाख यात्रियों ने सफर किया था और सारा रिकॉर्ड को तोड़ दिया था. इससे पहले 4 सितंबर 2023 को 71.03 लाख यात्रियों और 29 अगस्त 2023 को 69.94 लाख यात्रियों के सफर किया था.

कितना बड़ा है दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क

दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) का नेटवर्क लगातार बढ़ता जा रहा है. मौजूदा समय में नोएडा-ग्रेटर नोएडा कॉरिडोर और गुरुग्राम के रैपिड मेट्रो को

मिलाकर दिल्ली मेट्रो का संचालन 390.14 किलोमीटर रूट पर हो रहा है और 286 स्टेशनों पर यात्रियों को मेट्रो की सुविधा मुहैया की जा रही है. हालांकि, इसके बाद भी मेट्रो के आगे बढ़ने की रफ्तार कम नहीं हुई है और कई रूट पर अभी भी काम चल रहा है.

कितने बजे शुरू होती है दिल्ली मेट्रो की सर्विस

दिल्ली मेट्रो की सेवाएं (DElhi Metro Service Timing) आमतौर पर सुबह 5:30 बजे से शुरू हो जाती है और रात 11:30 बजे तक चलती है. हालांकि, हर स्टेशन पर पहली ट्रेन और अंतिम ट्रेन के समय अलग-अलग होते हैं. एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर मेट्रो की सेवाएं आमतौर पर सुबह 4.45 बजे शुरू होती हैं और रात 11.30 बजे तक चलती है. पीक टाइम (Peak Hours) में हर 2-3 मिनट में मेट्रो की सेवा मिलती है, जबकि नॉन पीक टाइम के दौरान ट्रेनों के बीच 5-10 मिनट का अंतर होता है.

कैसे होती है दिल्ली मेट्रो की मेंटेनेंस और सफाई

दिल्ली मेट्रो के मेंटेनेंस और सफाई (Delhi Metro Cleaning and Maintenance) के लिए कुल 14 डिपो बने हुए हैं, जहां रात 11 बजे से 1 बजे तक काम होता है. दिल्ली मेट्रो के हर डिपो (Delhi Metro Depot) में करीब 40 ट्रेनें मेंटेनेंस और सफाई के लिए आती हैं. हर डिपो में लगभग 100 लोग रोजाना इन ट्रेनों की सफाई और मेंटेनेंस का काम करते हैं.

दो फेज में किया जाता है मेट्रों का मेंटेनेंस

दिल्ली मेट्रो के मेंटेनेंस का काम दो फेस में किया जाता है. पहले फेज में ट्रेनों की सफाई की जाती है और दूसरे फेज में गड़बड़ी को ठीक किया जाता है. डिपो में आने के बाद ट्रेनों की धूल-मिट्टी की सफाई ऑटोमैटिक मशीन से की जाती है. इसके बाद ट्रेनों के फॉल्ट को चेक किया जाता है और ठीक किया जाता है. हालांकि, गड़बड़ी कहां ठीक की जाएगी, इसका फैसला कंट्रोल रूम में लिया जाता है और फिर ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि वे ट्रेन को किस ट्रैक पर खड़ी करें. दूसरे फेज में ही मेट्रो ट्रेन के सॉफ्टवेयर अपडेट, टेलिकॉम ऑपरेशन, व्हील्स की चेकिंग, सिग्नल सिस्टम, इलेक्ट्रिक सप्लाई, एयर कंडीशन और कोच की बॉडी की जांच भी की जाती है.

स्टेशनों की भी लगातार होती रहती है सफाई

मेट्रो ट्रेनों के अलावा दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी 286 स्टेशनों (Delhi Metro Stations) की सफाई लगातार होती रहती है. दिल्ली मेट्रो के कर्मचारी लगातार स्टेशन की सफाई में करते रहते हैं. इसके अलावा यात्रा के दौरान भी कर्मचारी मेट्रो ट्रेनों के अंदर सफाई करते रहते हैं।

इन 7 लक्षणों को भूलकर न करें करें इग्नोर, हो सकता है स्तन कैंसर

आमतौर पर शरीर के विभिन्न अंगों में होने वाले कैंसर को उन्हीं के नामों से जाना जाता है. ब्रेस्ट कैंसर इस गंभीर बीमारी का सबसे आम, लेकिन गंभीर प्रकार है. यह दुनियाभर में होने वाली महिलाओं की मौत का प्रमुख कारण है. ऐसा माना जाता है कि 5% से 10% तक ब्रेस्ट कैंसर के मामले आनुवंशिक होते हैं.

आधुनिक दौर की जीवन शैली और आज के खानपान के चलते कई तरह की बीमारियां समाज में पैदा हो रही हैं. उनमें से एक ब्रेस्ट कैंसर भी है. आंकड़ों के अनुसार कैंसर दुनियाभर में होने वाली मौतों का सबसे प्रमुख कारण माना जाता है. यह एक गंभीर बीमारी है, जो सही इलाज न मिलने पर जानलेवा साबित हो सकती है. आमतौर पर शरीर के विभिन्न अंगों में होने वाले कैंसर को उन्हीं के नामों से जाना जाता है. ब्रेस्ट कैंसर इस गंभीर बीमारी का सबसे आम, लेकिन गंभीर प्रकार है. यह दुनियाभर में होने वाली महिलाओं की मौत का प्रमुख कारण है.

इसकी कुछ मुख्य वजहों में पारिवारिक इतिहास, रेडिएशन के संपर्क में आना, मोटापा, शराब का सेवन आदि हैं. उम्र के साथ महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ता जाता है. ऐसा माना जाता है कि 5% से 10% तक ब्रेस्ट कैंसर के मामले आनुवंशिक होते हैं

इलाज में न करें देरी

उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में और आसपास के इलाकों से ऐसे मामले अक्सर आते रहते है. ब्रेस्ट कैंसर के इन शुरुआती लक्षणों से आप इसकी पहचान कर सकते हैं, जैसे स्तन में किसी तरह की गांठ होना. अगर आपको इस तरह का कोई लक्षण दिखाई दे, तो आप तुरंत अस्पताल पहुंचे. दून अस्पताल समय-समय पर जागरूकता अभियान चलाता रहता है और इसी के साथ ही दून अस्पताल में कीमोथेरेपी आदि जैसी सुविधाओं से कैंसर के मरीजों को राहत भी मिल रही है.

कम उम्र में भी हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर

दून अस्पताल में कैंसर विभाग के एचओडी डॉ दौलत सिंह ने जानकारी देते हुए कहा है कि सहारनपुर, बिजनौर, चकराता, देहरादून और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों से दून अस्पताल में काफी मरीज ब्रेस्ट कैंसर के आ रहे हैं. उन्होंने बताया कि पहले 45 से 50 की महिलाओ में ब्रेस्ट कैंसर की शिकायत आम होती थी लेकिन अब कम उम्र में भी ब्रेस्ट कैंसर से ग्रसित मरीज अस्पताल में इलाज के लिए आ रहे हैं.

मोटापा बन सकता है ब्रेस्ट कैंसर का कारण

डॉक्टर सिंह बताते हैं कि नेचुरल फूड से दूर होकर आधुनिक समाज में लोग पिज़्ज़ा, बर्गर आदि फास्टफूड का ज्यादा सेवन कर रहे हैं, जिनमें सैचुरेटेड फैट होता है. यही कैंसर का कारण बन सकता है. नेचुरल डाइट और प्रॉपर न्यूट्रिशन न मिलने पर सैचुरेटेड फैट बॉडी में इकट्ठा होता रहता है. व्यायाम नहीं करने से वह बर्न नहीं हो पाता है, जिससे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी हो सकती है. मोटापा होने से भी ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बना रहता है. डॉक्टर बताते हैं कि अगर इसमें सही से और वक्त पर ट्रीटमेंट ना किया जाए, तो व्यक्ति की मौत भी हो जाती है.

ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण

अंडरआर्म्स और ब्रेस्ट में कोई लम्प (Breast Lump) या गांठ बनना.

स्तनों या उसके आसपास के भाग में टाइटनेस और सूजन.

स्तनों के साइज या शेप में बदलाव.

ब्रेस्ट स्किन का ढीला होना या सिकुड़ जाना.

ब्रेस्ट निपल से डिस्चार्ज होना.

ब्रेस्ट निपल से डिस्चार्ज होना.

रोज सुबह उठकर करें सिर्फ एक काम, 40% तक घट जाएगा कोलेस्ट्रॉल, कब्ज से भी मिलेगा छुटकारा, सेहत होगी चकाचक

अच्छी आदतें और बेहतर खान-पान के जरिए आप कई बीमारियों से राहत पा सकते हैं. खाने-पीने का बेहतर रूटीन बनाया जाए, तो आप लंबे समय तक हेल्दी रह सकते हैं. कोलेस्ट्रॉल के मरीजों के लिए रोज सुबह फल खाने की आदत बेहद लाभकारी हो सकती है. इस बारे में कई रिसर्च में चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं.

सेब सेहत के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद फलों में शुमार होता है. इसमें तमाम पोषक तत्व होते हैं, जो शरीर को बीमारियों से बचाकर स्वस्थ रखने में मददगार साबित होते हैं. रोज सुबह 2 सेब खाने से आपको कई परेशानियों से राहत मिल सकती है. ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि कई रिसर्च में सेब के बेहतरीन फायदे सामने आए हैं. हाई कोलेस्ट्रॉल और कब्ज के मरीजों के लिए तो यह फल रामबाण साबित हो सकता है. अगर आप सेब खाने के शौकीन हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है.

साल 2019 में सामने आई एक स्टडी में पता चला कि रोज 2 सेब खाने से शरीर में जमे बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को काफी हद तक कम किया जा सकता है. सेब कोलेस्ट्रॉल की परेशानी से राहत दिलाकर हार्ट हेल्थ बूस्ट करता है. सेब खाने से लोगों को हार्ट डिजीज का खतरा कम हो सकता है. सेब में भरपूर मात्रा में फाइबर और पॉलीफेनॉल्स पाए जाते हैं, जो शरीर में जाकर सेहत को दुरुस्त करने में मदद करते हैं. ये पोषक तत्व हमारी खून की धमनियों को रिलेक्स करने में मदद करते हैं और इनमें जमे कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालने में मदद करते हैं.

यह रिसर्च ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग के शोधकर्ताओं ने इटली के वैज्ञानिकों से साथ मिलकर की थी. यह रिसर्च अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लीनिकल न्यूट्रिशन में प्रकाशित हुई थी. हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है, जब किसी रिसर्च में सेब और कोलेस्ट्रॉल के बीच सीधा संबंध देखने को मिला है. इससे पहले साल 2011 में यूएसए की फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों से रिसर्च की थी. इसमें पता चला था कि रोज 2 सेब खाने से बैड कोलेस्ट्रॉल यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन (LDL) लेवल 40 फीसदी तक कम हो सकता है. साल 2012 में ओहियो यूनिवर्सिटी की रिसर्च में भी ऐसे ही तथ्य सामने आए थे.

खास बात यह है कि रोज सेब खाने से कब्ज की समस्या भी दूर हो सकती है. सेब में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है. फाइबर एक ऐसा तत्व है, जो हमारे पाचन तंत्र को सुधारने में मदद करता है और पेट साफ करने में मदद करता है. कब्ज के मरीजों को अक्सर फाइबर से भरपूर फूड्स खाने की सलाह दी जाती है. सेब को इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए भी अच्छा माना जाता है. इसका सेवन करने से मेंटल हेल्थ भी बूस्ट हो सकती है. सभी लोग नियमित रूप से सेब का सेवन कर सकते हैं. हालांकि अगर आप किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, तो सेब खाने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह लें.

डायबिटीज महिलाओं के लिए अधिक घातक क्यों? डॉक्टर से जानें किन बीमारियों का बनता है कारण

डायबिटीज एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जो हाई ब्लड शुगर लेवल के कारण होता है. डायबिटीज से पीड़ित महिलाओं को वेजाइनल डिस्चार्ज, गुप्तांग में खुजली, दर्द, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, सेक्स ड्राइव में कमी और बार-बार पेशाब आना जैसे लक्षणों का अनुभव हो सकता है. आइए गायनेकोलॉजिस्ट से जानते हैं कई समस्याओं के बारे में-

दुनियाभर में डायबिटीज से पीड़ितों की फेहरित लंबी है. ताउम्र साथ रहने वाली यह बीमारी हर उम्र के महिला-पुरुष को अपना शिकार बना रही है. इसकी जद में आते ही इंसान को तमाम गंभीर बीमारियों शिकार बनाने लगती हैं. वैसे तो डायबिटीज की गंभीरता सभी में देखी जाती है, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट महिलाओं के लिए ये अधिक घातक बताते हैं. जी हां, महिलाओं में डायबिटीज हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, अंधापन, डिप्रेशन, यूटीआई और इंफर्टिलिटी की समस्याओं के हाई रिस्क में डाल सकती है. अब सवाल है कि डायबिटीज महिलाओं के कैसे घातक? किन बीमारियों का बढ़ता है खतरा? कैसे रखें शुगर लेवल मेंटेन? इस बारे में News18 को बता रही हैं राजकीय मेडिकल कॉलेज कन्नौज की गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. अमृता साहा-

यौन रोगों का सबसे अधिक जोखिम

डॉ. अमृता साहा के मुताबिक, डायबिटीज एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जो हाई ब्लड शुगर लेवल के कारण होता है. डायबिटीज महिलाओं के ओवरऑल हेल्थ पर प्रभाव डालती है. इससे पीड़ित होने पर महिलाओं को वेजाइनल डिस्चार्ज, योनि में खुजली, दर्द, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, सेक्स ड्राइव में कमी और बार-बार पेशाब आने जैसे लक्षणों का अनुभव हो सकता है. यही नहीं, मासिक चक्र में बदलाव से पीरियड्स लंबे और हेवी भी हो सकते हैं. इसलिए, उनके लिए एक हेल्थ लाइफस्टाइल को मेंटेन करने और अपने शुगर कंट्रोल लेवल को मॉनीटर करना जरूरी हो जाता है.

प्रजनन अंगों को होता है नुकसान

डायबिटीज में महिलाओं में वेजाइनल ल्यूब्रिकेशन कम हो जाता है, जिससे उन्हें इंटरकोर्स के दौरान दर्द हो सकता है. टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज दोनों ही पीरियड्स की अनियमितताओं और कम प्रजनन दर के लिए जिम्मेदार हैं. दरअसल, डायबिटिक महिलाओं में संक्रमण और फैलोपियन ट्यूब जैसे प्रजनन अंगों को नुकसान होने का खतरा अधिक होता है.

हार्ट अटैक का भी बनता है खतरा

हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, डायबिटीज से पीड़ित महिलाओं को भी दिल का दौरा पड़ने का खतरा अधिक होता है. इससे हार्ट अटैक का कारण भी बनता है. इसके अलावा, महिलाओं में डायबिटीज से अंधापन, गुर्दे की बीमारी और अवसाद जैसे लक्षण भी देखने को मिल सकते हैं.

ऐसे करें मेंटेन करें ब्लड शुगर लेवल

डाइटिशियन रितु त्रिवेदी के मुताबिक, आपकी हेल्दी डाइट शुगर लेवल को मेंटेन करने में कारगर हो सकती है. इसके लिए फाइबर से भरपूर खाना खाएं. अपने आहार में ताजे फल, सब्जियां, साबुत अनाज, फलियां और दाल शामिल करें. जितना संभव हो ऑयली, प्रोसेस्ड और डिब्बाबंद फूड आइटम्स से बचें. पैक्ड जूस, मिठाई, मिठाई, कोला और सोडा की जगह घर का बना ताजा जूस लेना चाहिए. ध्यान रखें कि वजन एक्सरसाइज और योग को जरूर करें. इससे वजन मेंटेन रहने के साथ डायबिटीज का जोखिम कम हो सकता है.

कैल्शियम की कमी होते ही महिलाओं के शरीर में दिखते हैं ये 6 बदलाव, तेजी से गलने लगता है ढांचा, जान लें वजह

पुरुषों की तुलना में महिलाओं के शरीर में कैल्शियम की कमी का खतरा अधिक होता है. कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर होने लगती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है. यही नहीं, बोन फ्रैक्चर का खतरा भी बढ़ जाता है.

कैल्शियम हमारे शरीर में मौजूद सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला मिनरल है जो बॉडी के बोन्स और दांतों के विकास के अलावा भी कई तरह के जरूरी कामों को करने में मदद करता है. बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों के लिए कैल्शियम सबसे अधिक जरूरी है. बच्चों के ग्रोथ में कैल्शियम काम आता है जबकि बुजुर्गों में बोन डेंसिटी को बढ़ाए रखने और फ्रैक्चर जैसी परेशानी से बचाने का यह काम करता है.

महिलाओं में कैल्शियम की कमी ज्यादा देखने को मिलती है. यह खान-पान में लापरवाही और बुरे लाइफस्टाइल के कारण होता है. हेल्थलाइन के मुताबिक, महिलाओं में अगर कैल्शियम की कमी होने लगती है तो उनकी हड्डियां कमजोर होने लगते हैं और फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है. 40 के बाद तो महिलाओं को अपने बोन डेंसिटी का बढ़ाए रखने के लिए खासतौर पर कैल्शियम रिच फूड खाना जरूरी है.

इसके लक्षणों की बात करें तो महिलाओं में कैल्शियम की कमी होने का पहला लक्षण है कि पीरियड के दौरान काफी पेन होना. हाइपरकैल्सीमिया होने की वजह से प्री मेंस्ट्रुअल क्रैम्प की परेशानी होने लगती है.

कैल्शियम की कमी होने पर दांत में दर्द या दांतों के गिरने की परेशानी शुरू हो जाती है. अगर आपके दांतों में भी एकाएक दर्द हो रहा है तो आप डाइट में कैल्शियमकी मात्रा को बढ़ाएं. कैल्शियम की कमी से ओरल प्रॉब्लम जैसे पेरियोडोंटल बीमारी भी हो सकती है.

महिलाओं की मांसपेशियों में अगर दर्द रहता है तो यह भी कैल्शियम की कमी का एक लक्षण है. कैल्शियम की कमी होने पर मसल्स में ऐंठन और क्रैंप की परेशानी शुरू हो जाती है. ऐसा हो तो महिलाएं अपनी डाइट का खास ख्याल रखें.

शरीर में कैल्शियम की कमी होने पर नाखूनों पर भी इसका असर दिखता है. नाखून हेल्दी नहीं दिखते और पीले पड़ने लगते हैं. यही नहीं, नाखून जल्दी कमजोर हो जाते हैं और बड़ी आसानी से टूटने लगते हैं.

हर वक्त थकान अनुभव होना भी शरीर में कैल्शियम की कमी का एक लक्षण हो सकता है. अगर आप भरपूर सोती हैं लेकिन फिर भी थकावट रहती है तो यह कैल्शियम की कमी का लक्षण हो सकता है.

इसके अलावा डिप्रेशन, हाथ-पैर का सुन्न हो जाना, झुनझुनी लगना, मेमोरी लॉस, कनफ्यूजन आदि भी कैल्शियम की कमी के लक्षण हैं. शरीर में कैल्शियम की कमी होने की वजहों की बात करें तो यह लंबे समय तक कैल्शियम की कमी होने, विशेषकर बचपन में, शरीर में कैल्शियम अवशोषण कम हो जाने, डाइट में कैल्शियम की कमी होने, महिलाओं में हार्मोनल बदलाव हो सकते हैं.

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उतरे

सुषमा रानी

बिजली दरों में वृद्धि और लोगों के सामने आ रही पानी की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सोमवार को दिल्ली की सड़कों पर उतर आए।

भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि आज हम दिल्ली के हर इलाके में, जहां भी इन बिजली कंपनियों के कार्यालय हैं, वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

यह उनके लिए चेतावनी है कि वे सावधान हो जाएं। अन्यथा, दिल्ली की जनता न तो बिजली कंपनियों को माफ करने वाली है और न ही दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को।

भाजपा ने कहा कि दिल्लीवासियों को महंगी बिजली दी जा रही है, लेकिन इसका कारण बिजली खपत में बढ़ोतरी होना नहीं है। उसका आरोप है कि बिजली महंगी होने का सबसे बड़ा कारण समय रहते अतिरिक्त बिजली की खरीद न किया जाना है, जबकि इसी की आड़ में छिपकर PPAC के जरिए हर साल अप्रत्यक्ष तरीके से बिजली बिल में बढ़ोतरी की जा रही है। पार्टी सोमवार को दिल्ली के सभी जिलों में बने बिजली दफ्तरों पर प्रदर्शन करेगी।

भाजपा के अनुसार, अब आम उपभोक्ताओं पर PPAC का बोझ 2015 में 1.5 फ़ीसदी से बढ़कर 37.5 फ़ीसदी हो चुका है। अलग-अलग कम्पनियों के द्वारा लगभग 8.75 फ़ीसदी की नई बढ़ोतरी के बाद यह 45 फीसदी तक हो जाएगा। पार्टी के अनुसार एक बार PPAC बढ़ाने के बाद इसे कभी वापस नहीं लिया जाता, जिससे इसकी मार बढ़ती जा रही है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने चेयरमैन को पत्र लिखकर PPAC पर पुनर्विचार करने की मांग की है।

केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में होगा उछाल

परिवहन विशेष न्यूज

परिवहन विशेष। एसडी सेठी। मोदी सरकार अपना 2023-24 का वित्तीय बजट 23 जुलाई को को पेश करने जा रही है। बजट में केंद्रीय कर्मचारियों की पगार में बंपर इजाफा होने की उम्मीद है। कर्मचारियों को सैलरी बढोतरी की बूस्टर डोज देने की सरकार की मंशा पर 23 को मोहर लगने वाली है। केंद्र सरकार की तरफ से अगर फिल्में फैक्टर में इजाफा किया गया तो फिर सैलरी में बल्ले-बल्ले बढोतरी तय मानी जा रही है। बता दें कि बेसिक सैलरी और भत्ते को मिलाकरजो पैसा बनता है वही सैलरी होती है। इससे कर्मचारियों को तगडा लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। बता दें कि केंद्र सरकार ने साल 2016 में फिटमेंट फैक्टर बढाने का फैसला लिया गया था।इसमें कर्मचारियो की कम से कम बेसिक वेतन 6 रूपये से बढकर 18000 रूपये पहुंच गया था। इस हिसाब सेञकरीब 12000रूपयेञका इजाफा किया गया था। अब न्यूनतम बेसिक सैलरी 26000 रूपये हो जाएगी।वह किसी बडी सौगात की तरह होगा। उम्मीद है कि फिटमैंट फैक्टर को 2.57 गुना से बढाकर 3.68 गुना किया जा सकता है। अगर फिटमेंट फैक्टर के बाद सैलरी बढोतरी 26000 रूपये हो जाती है तो बाकी भत्ता मे भी इजाफ़ा ए को मिलेगा।मंहगाई भत्ता बेसिक वेतन के 46 प्रतिशत के बराबर है। इससे कर्मचारियों के अकाउंट में बंपर रकम खाते में आएगी।

'कोमा में जा सकते हैं केजरीवाल', दिल्ली सरकार के मंत्री का बड़ा दावा

आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जेल में दो किलो वजन घटने का आरोप लगाया जिसे तिहाड़ जेल प्रशासन ने झूठा बताया। उसके बाद आतिशी ने प्रेसवार्ता कर दावा किया कि उनका शुगर लेवल लगातार गिरता जा रहा है। इससे वह कोमा में जा सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी मौत भी हो सकती है।

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (AAP) ने अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर तिहाड़ जेल प्रशासन और भाजपा पर गंभीर आरोप लगाया है। आप की वरिष्ठ नेता आतिशी ने कहा कि केजरीवाल कोमा में जा सकते हैं। उससे पहले पार्टी नेताओं द्वारा केजरीवाल का दो वजन कम होने का दावा किया था, जिनका जेल प्रशासन ने खंडन किया।

आतिशी ने किया दावा

आतिशी ने प्रेसवार्ता में कहा कि अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल पांच बार खतरनाक स्तर तक गया है। उनका शुगर लेवल 50 तक गिर गया है। इस स्तर तक गिरने से शुगर मरीज की 20-30 मिनट में मौत हो जाती है। इसलिए उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। अरविंद केजरीवाल जी डायबिटिक हैं, तिहाड़ जेल के Senior Medical officer की रिपोर्ट बता रही है कि उनको Body Ache हो रहा है, उनका वजन गिर रहा है, उनका Sugar लेवल कई बार गिर रहा है। अगर ऐसे ही होता रहा तो अरविंद केजरीवाल जी कोमा में जा सकते हैं, उन्हें Brain Stroke हो सकता है।

मैं pic.twitter.com/Ezb49yT6zs

— AAP (@AamAadmiParty) July 15, 2024

भाजपा पर लगाया गंभीर आरोप

भाजपा ने दिल्ली के बेटे और देश के नायक अरविंद केजरीवाल की जान को खतरे में डाल दिया है। अरविंद केजरीवाल डायबिटिक हैं, तिहाड़ जेल के वरिष्ठ मेडिकल अफसर की रिपोर्ट बता रही है कि उनको शरीर में दर्द हो रहा है। उनका वजन गिर रहा है और उनका शुगर लेवल कई बार गिर रहा है। अगर ऐसे ही होता रहा तो अरविंद केजरीवाल कोमा में जा सकते हैं, उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। आतिशी ने कहा, मैं भाजपा से कहना चाहती हूं कि भगवान से डरो और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य से खिलवाड़ मत करो।

भाजपा का पलटवार

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि अदालत में सुनवाई की तारीख नजदीक आते ही आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा और उनके स्वास्थ्य को लेकर को लेकर बयानबाजी शुरू कर देते हैं। आप नेता केजरीवाल का शुगर का स्तर गिरने और वजन कम होने जैसी स्वास्थ्य समस्या होने की बात करते हैं। सचदेवा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार मुख्यमंत्री द्वारा चयनित डाक्टरों की सलाह के आधार पर उन्हें दवा दी जाती हैं। वह तिहाड़ जेल में बंद हैं, परंतु भोजन उनके घर से आता है। इसके बाद भी यदि उनका वजन कम हो रहा है तो इसका अर्थ है कि उन्हें घर से पौष्टिक भोजन नहीं भेजा जाता है। यह जानबूझकर उन्हें कमजोर दिखाने के लिए किया जा रहा है जिससे कि उन्हें जमानत मिल सके।

भारत में महिलाओं के लिए नवोन्मेषी स्टार्टअप विचार : विजय गर्ग

भारत में 2020 के बाद से एक महत्वपूर्ण स्टार्टअप लहर देखी गई है। इसके अतिरिक्त, उद्यमशीलता शो 'शार्क टैंक इंडिया' के प्रसारण ने लोगों, विशेषकर महिलाओं को अपना व्यवसाय बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। आईबीईएफ के अनुसार, लगभग 20.37% भारतीय महिलाएं एमएसएमई मालिक हैं और आज श्रम बल में 23.3% का योगदान करती हैं। डेटा 2020 के बाद से भारत में महिला उद्यमियों के उदय का प्रतिनिधित्व करता है। उसी के प्रकाश में, हमने 2024 में महिलाओं के विचार के लिए कुछ अद्वितीय स्टार्टअप विचारों को सूचीबद्ध किया है।

महिलाओं के लिए अनोखे स्टार्टअप विचार

यहां 2024 में महिलाओं के लिए पांच नवीन और अद्वितीय स्टार्टअप विचार दिए गए हैं:

स्वास्थ्य देखभाल पेशे

हेल्थकेयर सेक्टर को कभी मंदी का सामना नहीं करना पड़ सकता. यह सबसे रोमांचक और लगातार विकसित होने वाले क्षेत्रों में से एक है जो कई स्टार्टअप अवसर प्रदान करता है। कोरोनोवायरस महामारी के बाद, लोग अपने स्वास्थ्य के बारे में अधिक चिंतित हो गए हैं और इस प्रकार स्वस्थ जीवन शैली अपना रहे हैं। आप एक पेशेवर प्रशिक्षक बन सकते हैं और अपना खुद का फिटनेस सेंटर शुरू कर सकते हैं। योग और ध्यान केंद्र, जिम और जुम्बा कक्षाएं कुछ ऐसे विकल्प हैं जिन पर आप विचार कर सकते हैं।

जुम्बा

खाद्य एवं पेय पदार्थ क्षेत्र

खाद्य एवं पेय पदार्थ उभरते क्षेत्रों में से एक है। महिलाओं के लिए इस उद्योग में व्यवसाय के ढेरों अवसर हैं। आप अपने स्टार्टअप के रूप में इंस्टाग्रामेबल कैफे, बेकरी, क्लाउड किचन, रेस्तरां, फूड ऑन व्हील और घर-आधारित खानपान सेवाएं शुरू कर सकते हैं।

बेकरी की दुकान

सौंदर्य देखभाल केंद्र

आत्म-देखभाल अब कोई विलासिता नहीं बल्कि समय की सख्त जरूरत है। महिलाओं को सौंदर्य देखभाल में शामिल होना पसंद है और इसलिए वे इस क्षेत्र में महान उद्यमी बन सकती हैं। यदि आप उन लोगों में से हैं जिन्हें सौंदर्य और त्वचा की देखभाल पसंद है तो आपके लिए ढेर सारे अवसर इंतजार कर रहे हैं। स्पा और सैलून सेंटर, ब्राइडल मेकअप स्टूडियो और नेल आर्ट स्टूडियो कुछ ऐसे विकल्प हैं जिन पर आप इस क्षेत्र में विचार कर सकते हैं।

कला और हस्तशिल्प

यदि आप कला और हस्तशिल्प की प्रतिभा से संपन्न व्यक्ति हैं तो आपके पास इस क्षेत्र में स्टार्टअप के कई अवसर हैं। आप अपने हस्तशिल्प, कलाकृतियाँ, हस्तनिर्मित आभूषण, मनके आदि बेच सकते हैं।

सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य शैक्षिक स्तंभकार मालौत

राहुल गांधी की सोच ''नेता बनो-नेता चुनो'' के अनुसार लोकतांत्रिक प्रक्रिया के चुनाव संगठन में चुनाव कराकर सबको बराबर मौका दिया जाना चाहिए: देवेन्द्र यादव

सुषमा रानी

नई दिल्ली, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के सदस्यता अभियान के अंतर्गत दिल्ली प्रदेश युवा कांग्रेस के सदस्यता अभियान को लॉच करते हुए कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी की सोच ''नेता बनो-नेता चुनो'' की शुरुआत के साथ लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सबको बराबर मौका दिया जाना चाहिए। संगठन में लोकतंत्र को आतंरिक रुप से प्रक्रिया में लाकर राहुल जी का मकसद छोटे से छोटा कार्यकर्ता चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेकर अपनी काबलियत के अनुसार बड़े से बड़ा पद हासिल कर सकता है।

दिल्ली युवा कांग्रेस सदस्यता अभियान की शुरुआत के मौके पर प्रदेश अध्यक्ष देवेन्द्र यादव के साथ कम्युनिकेशन विभाग के चेयरमैन एवं पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज, आईवाईसी के महासचिव दिल्ली प्रभारी पूर्ण चन्द्र पांधी ''पोको'', सचिव प्रभारी खुशबु शर्मा, दिल्ली प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष रणविजय सिंह लोचव, आईवाईसी सचिव रिषी भारद्वाज, पी.आर.ओ. मुकुल गुप्ता, आईवाईसी के चुनाव आयुक्त मकसूद और दिल्ली प्रदेश युवा कांग्रेस एक्टिंग अध्यक्ष शुभम शर्मा सहित भारी संख्या में युवा कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद थे।

उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली प्रदेश युवा कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ कि दिल्ली देश की राजधानी है, यहां किया गया हर काम संदेश बनकर फैलता है, सभी कार्यकर्ता युवा कांग्रेस की अत्यधिक सदस्यता करके रिकॉड तोड़ मेम्बरशिप करें ताकि दिल्ली प्रदेश युवा कांग्रेस को एक कर्मठ और सुदृढ़ कार्यकारिणी मिल सके। उन्होंने कहा कि यह राहुल जी की सोच का ही नतीजा रहा कि पिछले कुछ सालों से युवा कांग्रेस में चुनाव प्रक्रिया को शुरु किया जिसमें कॉमन वर्कर को प्रदेश की नुमाईंदगी करने का मौका मिला है।

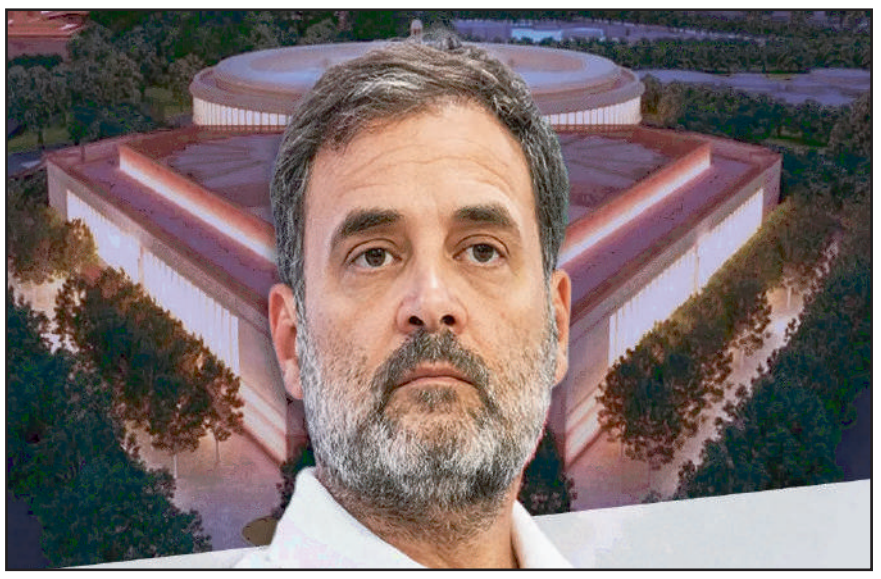

उन्होंने कहा कि यहां युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अनुरोध करना चाहता हूँ कि युवा कांग्रेस में लोकतांत्रिक प्रक्रिया द्वारा चुनाव की परम्परा और नियमों को शुरु किया गया है, दिल्ली में साफ सुथरा चुनाव आपसी सहयोग से लड़े और योग्य उम्मीदवार प्रदेश, जिला, विधानसभा और ब्लाक स्तर पर चुनकर दिल्ली में युवा कांग्रेस की एक मजबूत टीम का गठन करने में सहयोगी बनें। उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस के चुनाव में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी हर संभव सहयोग करेगी।

उन्होंने कहा कि आने वाला वक्त चुनौती भरा है, अगले वर्ष फरवरी में दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है, हमें भाजपा की तानाशाह और आम आदमी पार्टी की भ्रष्टाचारी केजरीवाल सरकार के सामने खड़ा होकर मजबूती से लड़ना होगा, जिसके लिए युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता की सकरात्मक भूमिका और सक्रियता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस राजनीतिक पृष्ठभूमि के साथ सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन भी बखूबी निभाती आई है। यादव ने मौजूद प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष रणविजय सिंह लोचव का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि कोविड के मुश्किल समय में जब अपना पदभार संभाला था, पूरी दिल्ली प्रदेश युवा कांग्रेस की टीम ने आगे बढ़कर दिल्लीवालों की की हर संभव मदद की थी।

केजरीवाल की सेहत पर आप के संजय सिंह में उबाल

परिवहन विशेष। एसडी सेठी।

आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता संजय सिंह ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि वह जेल में बंद आप के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सेहत से खिलवाड कर रही है। उनके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने की साजिश की जा रही है। उनके शूगर लेबल समेत वजन में भी लगातार गिरावट होने के बावजूद उन्हें चिकित्सा सहायता नहीं मिल रही है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि किसी भी कैदी, मरीज की मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक करना अपराध है।जेल प्रशासन कई बार दिल्ली के सीएम की मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक कर चुका है।

इससे तो ये ही साबित होता है कि अरविंद केजरीवाल की जिंदगी से खिलवाड करने की साजिश रची जा रही है।इस पर कारवाई होनी चाहिए। संजय सिंह के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा द्वारा केजरीवाल की सेहत के खिलाफ षडयंत्र रचा जा रहा है। जेल में केजरीवाल के साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती है। सिंह ने बताया कि आल इंडिया इंस्टिट्यूट आफ मेडीकल साइंस(एम्स) के डॉक्टरो के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि केजरीवाल का वजन 8.5 किलोग्राम कम हो गया है।वही

शूगर लेबल भी कई बार 50 के नीचे तक गया है। दिल्ली की केबिनेट मंत्री आतिशी ने भी शूगर लेबर समेत वजन कम होने की खतरनाक स्थिति है। आतिशी ने कहा कि अगर शूगर लेबल कम होने से अगर केजरीवाल को स्ट्रोक आता है ,या उनके दिमाग को नुकसान पहुंचता है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? वहीं इस बावत तिहाड जेल अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि आप नेता सीएम केजरीवाल की सेहत स्थिति में संबंधित निराधार आरोप लगा रहे है। जेल अधिकारियों के मुताबिक केजरीवाल की शूगर के स्तर की नियमित रूप से निगरानी की जा रही थी। तिहाड जेल नंबर-2 के अधीक्षक के मुताबिक अदालत के आदेशों के अनुसार, घर का बना खाना सहित चिकित्सकीय रूप से निर्धारित आहार का पालन कर रहे हैं। हां थोडा सा वजन कम हुआ है लेकिन उनका स्वास्थ्य बिल्कुल नोर्मल बना हुआ है। इस बावत दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल की जमानत के लिए बेताब आप नेता रोज रटा रटाया राग अलापते है। जो कल संजय सिंह ने बोला वो आतिशी ने दोहराया है। पर चुनाव पूर्व जमानत पर बाहर आए केजरीवाल ने हर दिन प्रचार किया था,उन्हें एक दिन भी किसी अस्पताल में जाते नहीं देखा। सचदेवा ने कहा कि सुप्रीमकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी संबंधित सीबीआई मामले में वह जेल में है।

क्रिकेट मैच फिक्सिंग कांड-2000 का आया फैसला

परिवहन विशेष। एसडी सेठी।

आज से 24 साल पहले क्रिकेट मैच फिक्सिंग कांड में अदालत की तरफ से अब फैसला आ गया है। कोर्ट ने चार आरोपियो के खिलाफ आरोप तय किए हैं। कोर्ट के मुताबिक साल 2000 में भारत- दक्षिण अफ्रीका टेस्ट और वन डे सीरीज के कुछ मैच फिक्स किए गए थे। साथ ही कुछ मैचो को फिक्स करने की कोशिश की गई थी।मामले में 4 आरोपियो के खिलाफ घोखाधडी और आपराधिक साजिश के आरोप तय किए गए है।इनमें लंदन स्थित सट्टेबाज और मुख्य साजिशकर्ता संजीव चावला ,T- सीरीज संस्थापक गुलशन कुमार के भाई और एक्टर कृष्ण कुमार के नाम भी शामिल है। दिल्ली की पटियाला हाउस डिसट्रिक्ट कोर्ट ने 68 पेज का आदेश जारी किया है।इसमें संजीव चावला,कृष्ण कुमार ,दिल्ली स्थित सट्टेबाज राजेश कालरा,और सुनील दारा उर्फ बिट्टू की कथित भूमिका के बारे में बताया गया है।मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने साल-2000 के क्रिकेट मैच फिक्सिंग कांड पर खासा बावेला मचा था। उसमें भारतीय टीम के फास्ट बॉलर श्रीनाथ का नाम भी आया था। दिल्ली पुलिस ने इस सिलसिले में 2013 में चार्जशीट दायर की थी।इसमें दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कैप्टन हैंसी क्रोन्ये का नाम भी शामिल था।जिनकी 2002 में एक प्लेन हादसे में मौत हो गई थी। उल्लेखनीय है कि संजीव चावला को फरवरी-2020 में भारत को सौंप दिया था। कोर्ट के मुताबिक संजीव चावला ने हैंसी कोरोन्ये के साथ मिलीभगत करके सट्टेबाजो और मैच फिक्स करने वालो के बीच बिचौलिए का काम किया था। ये पूरी मैच फिक्सिंग साऊथ अफ्रीका के कैप्टन हैंसी क्रोनिये की सक्रिय भागीदारी के बिना भी संभव नहीं होता।उन्होने किंग्स जांच आयोग के सामने अपनी भूमिका और संलिप्तता की बात मान ली थी। सभी आरोपी एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में रहे और मैच फिक्स कराने की साजिश रची।

12 स्कूलों की मान्यता होगी रद्द, चार महीने बीतने के बाद भी नहीं ले रहे दाखिले; कमिटी गठित

बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पंवार की ओर से जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा को अवगत कराया गया कि 12 स्कूल अभी तक दाखिला देने में आनाकानी कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने ऐसे स्कूलों की मान्यता छीनने के लिए कमिटी गठित कर शासन को रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं। एसडीएम वेद प्रकाश पांडे की अध्यक्षता में कमिटी का गठन किया गया है।

ग्रेटर नोएडा। आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को शिक्षा के अधिकार अधिनियम(आरटीई) के तहत दाखिला नहीं देने वाले स्कूलों पर जिला प्रशासन सख्त हो गया है। चार महीने बीत जाने के बाद भी दाखिले नहीं करने वाले 12 स्कूलों पर मान्यता रद्द की कार्रवाई की तलवार लटक गई है। बता दें चार चरण में निजी स्कूलों में आरटीई के तहत आवंटित 5061 सीटों में से केवल 25,00 छात्रों के दाखिले अब तक हुए हैं।

बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पंवार की ओर से जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा को अवगत कराया गया कि 12 स्कूल अभी तक दाखिला देने में आनाकानी कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने ऐसे स्कूलों की मान्यता छीनने के लिए कमिटी गठित कर शासन को रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं। एसडीएम वेद प्रकाश पांडे की अध्यक्षता में कमिटी का गठन किया गया है।

कमिटी स्कूलों को एक हफ्ते में करेगी जवाब तलब

कमिटी में जिला दिव्यांग अधिकारी आशीष कुमार और कुमारी मायावती राजकीय कन्या इंटर कालेज की प्राचार्य छवि सिंह को सदस्य बनाया गया है। कमिटी स्कूलों को नोटिस भेजकर एक सप्ताह में जवाब तलब करेगी। जवाब नहीं आने पर जिलाधिकारी से मान्यता छीनने की सिफारिश करेगी। जिलाधिकारी शासन को मान्यता रद्द करने के लिए भेज देंगे।

इन स्कूलों की रद्द होगी मान्यता

बाल भारती पब्लिक स्कूल नोएडा, दिल्ली पब्लिक स्कूल ग्रेटर नोएडा वेस्ट, द मिलेनियम स्कूल नोएडा, रामाज्ञा स्कूल नोएडा, समसरा द वर्ल्ड एकेडमी ग्रेटर नोएडा, राघव ग्लोबल स्कूल नोएडा, दरबारी लाल फाउंडेशन वर्ल्ड स्कूल ग्रेटर नोएडा, शिव नादर स्कूल नोएडा, संस्कार रोजा जलालपुर, फार्चून वर्ल्ड स्कूल नोएडा, आर्मी पब्लिक स्कूल नोएडा और आक्सफोर्ड ग्रीन पब्लिक स्कूल ग्रेटर नोएडा पर मान्यता प्रत्याहरण की कार्रवाई होगी।

इन स्कूलों ने नहीं लिए एक भी दाखिले

स्कूल	सीट	दाखिले
द मिलेनियम स्कूल, नोएडा	15	0
रामाज्ञा स्कूल, नोएडा	28	0
दरबारी लाल फाउंडेशन वर्ल्ड स्कूल, ग्रेटर नोएडा	10	0
संस्कार रोजा, जलालपुर	8	0
फार्चून वर्ल्ड स्कूल, नोएडा	10	0
आर्मी पब्लिक स्कूल, नोएडा	7	0

इन 12 स्कूलों को कई बार नोटिस दिए गए, लेकिन इन्होंने दाखिले अब तक नहीं किए। जिलाधिकारी ने सभी स्कूलों पर मान्यता प्रत्याहरण करने के लिए कमेटी का गठन कर दिया है। कमेटी की रिपोर्ट आते ही इन स्कूलों की मान्यता रद होगी। - राहुल पंवार, बेसिक शिक्षा अधिकारी

सर्विस रोड ब्लॉक कर विंटेज कार से परोसी शराब, वीडियो वायरल होने के बाद चार गिरफ्तार

रविवार शाम बैंक्वेट हॉल में शादी समारोह का आयोजन था। बड़ी संख्या में लोग शादी में शामिल होने आए थे। कार्यक्रम में आए लोगों के बड़ी संख्या में वाहन सड़क किनारे खड़े थे। इसके चलते लोगों को कई घंटों तक जाम का सामना करना पड़ा। जाम का मुख्य कारण बैंक्वेट हॉल के निकट सर्विस रोड को ब्लाक करके विंटेज कार के जरिये लोगों को शराब पिलाना था।

नोएडा। कोतवाली सेक्टर-113 क्षेत्र के सेक्टर-73 स्थित शौर्य बैंक्वेट हॉल के निकट सर्विस रोड ब्लॉक कर विंटेज कार से शराब परोसने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। बैंक्वेट हॉल के मैनेजमेंट व बार संचालक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चार लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने विंटेज कार भी जब्त कर ली है।

रविवार शाम बैंक्वेट हॉल में शादी समारोह का आयोजन था। बड़ी संख्या में लोग शादी में शामिल होने आए थे। कार्यक्रम में आए लोगों के बड़ी संख्या में वाहन सड़क किनारे खड़े थे। इसके चलते लोगों को कई घंटों तक जाम का सामना करना पड़ा। जाम का मुख्य कारण बैंक्वेट हॉल के निकट सर्विस रोड को ब्लाक करके विंटेज कार के जरिए लोगों को शराब पिलाना था।

खुलेआम शराब पीने का वीडियो वायरल

इस संबंध में आबकारी विभाग से भी कोई लाइसेंस नहीं लिया गया था। बिना अनुमति विंटेज कार से खुलेआम शराब पिलाए जाने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गया था। वीडियो में कुछ लोगों को शराब परोसी जा रही थी, वहीं लोग सड़क पर जाम से जूझ रहे थे। वीडियो के जरिये संज्ञान में आने पर हरकत में आई पुलिस सोमवार दिनभर विंटेज कार और उसके बारे में जानकारी करती रही।

विंटेज कार को सीज किया गया

एडीसीपी मनीष कुमार मिश्र ने बताया कि शौर्य बैंक्वेट हॉल के बाहर आयोजकों द्वारा विंटेज कार से खुले में शराब का सेवन कराया जा रहा था।

... तो इस वजह से किशोर बन रहे हिंसक, किशोरों ने युवक-युवतियों को मार डाला; जानिए पूरा मामला

बच्चों और किशोरों के हिंसक होने का कारण एक वीडियो गेम्स और रील्स भी है। किशोर इंटरनेट मीडिया पर आए दिन हिंसक वीडियो बनाकर पोस्ट करते हैं। गुरुग्राम में पिछले 15 दिनों में दो ऐसे मर्डर हुए हैं जिन्हें किशोरों ने किया है। उसमें उनके हिंसक होने का कारण हिंसक वीडियो भी है। इस तरह किशोर हिंसक होकर परिवारों को उजाड़ दे रहे हैं।

गुरुग्राम। आज इंटरनेट मीडिया पर हजारों ऐसी रील्स हैं, जिसमें हिंसा की प्रवृत्ति दिखाई जाती है। वीडियो गेम्स और फिल्मों की कॉपी कर बड़ों के साथ-साथ किशोर भी उन्हीं के तरीके से रील्स बनाकर इंटरनेट मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं। इससे वह खुद तो बिगड़ ही रहे हैं और साथ ही निजी जिंदगी में भी थोड़ी सी अनबन होने पर किशोर हिंसक प्रवृत्ति की वारदात कर दूसरे परिवारों को भी उजाड़ रहे हैं।

अभी हाल ही में 15 दिनों में दो ऐसे मामले आए, जिसमें किशोरों ने एक लड़की और एक लड़के की जान ले ली। एक जुलाई को जहां 16 वर्षीय किशोर ने राजेंद्रा पार्क थाना क्षेत्र में पास ही के फ्लैट में रहने वाली नौ वर्षीय लड़की की जान ले ली। वहीं, 10 जुलाई की रात सेक्टर-40 में 15 वर्षीय किशोर ने अपने 16 वर्षीय दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। दोनों ही मामलों में किशोर हत्यारोपित हैं।

ऑनलाइन वीडियो देखकर रची साजिश

राजेंद्रा पार्क वाले हत्याकांड में नाबालिग आरोपी वीडियो गेम्स देखता था और मोबाइल पर ऑनलाइन जुआ भी खेलता था। जुए में वह अपने दोस्त के 60 हजार रुपये हार गया था। इसलिए उसने ऑनलाइन वीडियो देखकर चोरी की साजिश रची। चोरी करने पहुंचे आरोपी ने लड़की से छेड़छाड़ भी की। उसके चिल्लाने पर नाबालिग ने लड़की की चुन्नी से गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को बेड पर डालकर आग लगा दी।

लड़की के सामने अपमान नहीं सह सका किशोर

वहीं, सेक्टर-40 में लड़की के सामने अपने साथ गलत व्यवहार होने पर किशोर को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उसने दोस्त की हत्या की साजिश रच ली। उसने नया चाकू खरीदा और बीयर के बहाने घर से बुलाकर अपने साथ ले गया। यहां उसने चाकू से गला काटकर हत्या कर दी। उसने गले के साथ-साथ पेट भी गहरे घाव किए। सूत्रों के अनुसार यह भी इंटरनेट मीडिया से काफी प्रभावित था। आरोपित की दोस्ती भी उस लड़की से इंस्टाग्राम पर ही हुई थी।

अकेलेपन के कारण बच्चे देखते हैं मोबाइल

गुरुग्राम जैसे बड़े शहरों में घर का खर्च चलाने के लिए दंपती काम करते हैं, ऐसे में बच्चे अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं। वे मोबाइल और टीवी में व्यस्त होकर किसी भी तरह का वीडियो देखते हैं और फिर उसी तरह की हरकते करते हैं। वहीं माता-पिता में अक्सर झगड़े भी बच्चों की मनोदशा पर प्रभाव डालते हैं।

सलाह-

बच्चों को ज्यादा देर मोबाइल देखने के लिए न दें

समय-समय पर चेक करें कि बच्चे किस तरह का कंटेंट देख रहे हैं

लैपटॉप या कंप्यूटर पर भी नजर बनाए रखें

वह किससे बात कर रहे हैं, किसके साथ बच्चों की दोस्ती है, उनसे भी समय-समय पर बातचीत करें

स्कूल में बच्चों के बारे में फीडबैक लें

किशोरों में हिंसक प्रवृत्ति कई वजहों से बढ़ती है। आमतौर पर जितने भी रील्स इंटरनेट मीडिया पर आते हैं, वह हिंसा से भरे होते हैं। कहीं मारपीट के वीडियो हैं तो कहीं गोली मारने के। बच्चे इन्हीं सब चीजों से सीखते हैं। उनका हिंसक प्रभाव वीडियो गेम्स भी बढ़ता है। इस समय तो थ्रीडी वीडियो गेम्स आ गए हैं। इसमें बच्चा अपना अवतार जेनरेट कर खेलता है।

थाइलैंड में चला रहा था गैंग, इशारों पर कराता हत्याएं; पेरोल लेकर फरार हुआ गैंगस्टर काला खैरमपुरिया गिरफ्तार

कुख्यात गैंगस्टर काला खैरमपुरिया थाइलैंड में रहकर भाऊ गैंग चला रहा था। हरियाणा की एसटीएफ टीम खैरमपुरिया को थाइलैंड से लेकर गुरुग्राम आ गई है। पुलिस ने उसे शुक्रवार रात दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। उसने सोनीपत दिल्ली और हिसार में फायरिंग की घटनाएं इसके कहने पर गुर्गों ने अंजाम दी थीं। 2018 में हत्या के मामले में राजस्थान के हनुमानगढ़ अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई थी।

गुरुग्राम। हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली पुलिस के लिए सिरदर्द बने कुख्यात गैंगस्टर काला खैरमपुरिया को एसटीएफ हरियाणा की टीम ने शुक्रवार रात दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। 2020 में पेरोल पर बाहर आने के बाद वह फरार था और थाइलैंड में रहकर भाऊ गैंग चला रहा था। थाइलैंड में पहचान होने के बाद वहां से इसे लाया गया।

काला के ऊपर हत्या, हत्या के प्रयास, रंगदारी व अन्य से संबंधित 20 से अधिक मामले तीनों राज्यों में दर्ज हैं। यह हिसार के खैरमपुरिया का रहने वाला है। इसके कहने पर ही भाऊ गैंग के गुर्गों ने हिसार में बीते दिनों कार डीलर शोरूम के बाहर फायरिंग की थी।

स्पेशल टास्क फोर्श की गई तैयार

हरियाणा एसटीएफ के डीआइजी सिमरदीप सिंह ने गुरुग्राम स्थित एसटीएफ के हेडक्वार्टर में बताया कि स्पेशल टास्क फोर्स ने खैरमपुरिया को गिरफ्तार कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। राकेश उर्फ काला खैरमपुरिया गंभीर और हिंसक अपराधों में व्यापक रूप से शामिल था।

भारत में रहकर कई देशों में अपराध किए

पेरोल के बाद फरार होकर वह भारत में रहते हुए और बाद में दूसरे देशों दुबई, आर्मेनिया और थाईलैंड से भारत में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। काला का आपराधिक रिकॉर्ड 2014 से शुरू हुआ था। उस पर डकैती, लूट, हत्या और अवैध हथियार रखने के आरोप हैं।

आजीवान कारावास की काट रहा था सजा

2015 में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के थाना भादरा में एक हत्या के मामले में उसे 2018 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। दो साल सजा काटने के बाद वह 2020 में पेरोल पर जेल से बाहर आकर फरार हो गया। इस दौरान उसने हरियाणा और पड़ोसी राज्यों में अपनी आपराधिक गतिविधियों को और बढ़ा दिया।

वर्ष 2021 में फतेहाबाद जिले के थाना भकला के गांव दड़ौली में मास्टर पीके हत्याकांड में उसका नाम सामने आया। इस मामले में उसे वर्ष 2023 में अदालत ने उद्घोषित अपराधी घोषित किया गया।

फर्जी पासपोर्ट बनवाकर थाइलैंड हुआ फरार

काला खैरमपुरिया ने वर्ष 2023 की शुरुआत में एक एजेंट से फर्जी पासपोर्ट बनवाया और थाइलैंड फरार हो गया। इसने विदेश में रहते हुए भी गिरोह का संचालन जारी रखा। काला के संपर्क हिमांशु भाऊ और नीरज फरीदपुरिया गिरोह जैसे कुख्यात आपराधिक गिरोहों से थे।

उनके साथ राकेश उर्फ काला ने हत्याओं और जबरन वसूली सहित कई हाई-प्रोफाइल अपराधों को अंजाम दिया। दिसंबर 2023 में सोनीपत में एक गांव के सरपंच की हत्या, जनवरी 2024 में गोहाना में एक मशहूर मिठाई की दुकान पर गोलीबारी, मुरथल में एक ढाबे पर दिनदहाड़े हत्या और पिछले महीने दिल्ली के राजौरी गार्डन में एक बर्गर आउटलेट पर एक व्यक्ति की निर्मम हत्या की साजिश भी काला ने ही रची थी।

कार शोरूम के बाहर कराई गोलीबारी

अवैध वसूली को लेकर 24 जून 2024 को तीन नकाबपोश हमलावरों ने हिसार में महिंद्रा कार शोरूम के बाहर गोलीबारी की थी। एसटीएफ की जांच में पता चला कि राकेश उर्फ काला खैरमपुरिया ही इस घटना का मास्टरमाइंड है। जांच से पता चला कि राकेश ने ही हथियारों की व्यवस्था कर हमलावरों को पहुंचाया। इसके बाद उसने अपने इंस्टाग्राम से कार शोरूम पर हमले की जिम्मेदारी भी ली थी।

पहचान होने के बाद जारी कराया इंटरपोल नोटिस

कई मामलों में नाम आने के बाद एसटीएफ ने काला की तलाश शुरू की। एक फर्जी पहचान का पता लगाया। काला ने इसी आधार पर अपना पासपोर्ट बनवाया था। उसकी पहचान होने पर टीम ने उसकी यात्रा के बारे में जानकारी जुटाई।

सूत्रों के अनुसार, थाइलैंड में उसे ट्रेस किया गया। फौरन गृह मंत्रालय से उसके खिलाफ इंटरपोल नोटिस और अंतरिम गिरफ्तारी वारंट जारी कराया। इस बीच एसटीएफ टीम ने उसका फर्जी पासपोर्ट रद्द कराया और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर उसे भारत लाने के प्रयास तेज किए।

उसे गुरुवार को थाइलैंड से भारत प्रत्यर्पित किया गया। इसके बाद टीम ने उसे दिल्ली एयरपोर्ट गिरफ्तार कर लिया। उसे कोर्ट में पेश कर सात दिन के रिमांड पर लिया जाएगा। इस दौरान उससे उसके गिरोह के बारे में और जानकारी पता चल सकेगी।

काला खैरमपुरिया के खिलाफ दर्ज मामले

दो नवंबर 2014: हिसार के सदर थाने में धोखाधड़ी व अन्य में केस

11 फरवरी 2015 हिसार के सदर थाना क्षेत्र में लूट

23 फरवरी 2015 राजस्थान के हनुमानगढ़ के थाना भादरा में हत्या, इस मामले में इसे दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई

तीन मार्च 2015: हिसार के आदमपुर में लूट

15 मई 2015 हिसार के अशोका थाना क्षेत्र में मारपीट

राजस्थान के बीकानेर के थाना बीचवाल में पेरोल अधिनियम के तहत केस दर्ज

एक मार्च 2021: फतेहाबाद के भट्टू थाना क्षेत्र में हत्या, इस मामले में कोर्ट से उद्घोषित अपराधी घोषित किया गया

दो मार्च 2021: राजस्थान के हनुमानगढ़ के भिरानी में वसूली

27 जनवरी 2022: सिरसा के थाना नाथुसरी चौपटा में जानलेवा हमला, मारपीट

दो दिसंबर 2023 : हिसार के सदर थाना क्षेत्र के गांव खरर में शराब ठेकेदार की हत्या

11 दिसंबर 2023 : सोनीपत के थाना बरौदा क्षेत्र में सरपंच राजेश की हत्या

21 जनवरी 2024: सोनीपत के गोहना में जानलेवा हमला

10 मार्च 2024 में सोनीपत के मुरथल क्षेत्र में हत्या

24 जून 2024 में हिसार में कारोबारी के शोरूम के बाहर फायरिंग व जानलेवा हमला

तीन साल में योगी आदित्यनाथ कितने बदल पायेंगे हालात

अजय कुमार

लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में काफी नुकसान उठाना पड़ा। यूपी की वजह से केंद्र में मोदी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बन पाई, जो बीजेपी यूपी में 80 सीटें जीतने का सपना पाले हुए थी, वह 33 सीटों पर सिमट गई। बीजेपी का ग्राफ इतनी तेजी से गिरा की अब तो विपक्षी नेता खासकर राहुल गांधी और अखिलेश यादव तो दिल्ली में मोदी को सबक सिखाने के पश्चात तीन साल बाद 2027 में योगी को भी धूल चटाने की बात करने लगे हैं। 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव होने हैं और तब योगी की प्रतिष्ठा दांव पर होगी। 2027 के चुनाव में जहां राहुल गांधी और अखिलेश यादव बढ़े हुए मनोबल के साथ मैदान में उतरेंगे, वहीं बीजेपी को 2024 के नतीजे कचोटते रहेंगे, जबकि भारतीय जनता पार्टी 2024 जैसे चुनावी नतीजे 2027 विधानसभा चुनाव में नहीं देखना चाहती है। इसीलिये बीजेपी आलाकमान के साथ-साथ सीएम योगी आत्यिनाथ उन मुद्दों की धार कुंद करने में लग गये हैं जिसके सहारे कांग्रेस-सपा गठबंधन ने बीजेपी को आईना दिखाया था।

लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने संविधान, दलित ओबीसी आरक्षण, बेरोजगारी, महंगाई को बीजेपी के खिलाफ सबसे मजबूत चुनावी हथियार बनाया था। अबकी से राहुल के मुंह से अडानी-अंबानी, नोटबंदी, राफेल विमान खरीद भ्रष्टाचार, चौकीदार चोर है, जैसे तमाम जुमले सुनने को नहीं मिले थे। राहुल गांधी के साथ-साथ अखिलेश यादव भी अपनी जनसभाओं में दो ही बातें दोहराते रहे, पहला मोदी को 400 सीटें मिली तो वह संविधान बदल देंगे, दूसरा दलितों और ओबीसी को मिलने वाला आरक्षण खत्म कर दिया जायेगा। इसके अलावा राहुल की महिलाओं को 8500 रूपये प्रति माह देने की गांरटी ने भी बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया। चुनाव बाद भी जिस तरह से राहुल गांधी संविधान की किताब लिये घूम रहे हैं उसकी काट के लिये अब मोदी सरकार ने इमरजेंसी के 50 वर्ष पूरे होने के मौके पर कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। मोदी के मंत्री से लेकर छोटे-बड़े सभी नेता लगातार बता रहे हैं कि 1975 में किस तरह से तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार ने इमरजेंसी लगाकर संविधान की आत्मा को तार-तार कर दिया था। सदन में तो इमरजेंसी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव तक पास हो गया। सबसे खास बात यह रही कि मोदी सरकार जब इमरजेंसी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाई तो इसके खिलाफ कांग्रेस सदन में अकेले ही खड़ी नजर आई। राहुल के सबसे मजबूत साथी समझे जाने वाले सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी इमरजेंसी मुद्दे पर कांग्रेस के साथ नहीं गये।

बहरहाल, आम चुनाव में इंडी गठबंधन के कुछ दमदार और असरदार साबित हुए मुद्दों की धार को मोदी सरकार कम करने में लगी है तो दूसरी ओर गठबंधन के कुछ मुद्दों की हवा निकालने के लिये योगी सरकार ने अपने कंधों पर जिम्मेदारी ले रखी है। योगी ने इसके लिये अभी से सरकार के पेंच कसना शुरू कर दिये हैं। संगठन स्तर पर भी काम चल रहा है। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के शुरुआती तीन-चार महीनों में सम्पन्न होना है। इस हिसाब से सरकार के पास तीन साल से भी कम का समय बचा है। यह तय माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से सबक लेते हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी खराब छवि वाले विधायकों का टिकट काटने में भी आलाकमान परहेज नहीं करेगा। गौरतलब हो, हाल में सम्पन्न लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उम्मीद से काफी कम सीटें मिली थीं। चुनाव आयोग ने जो आकड़े जारी किये हैं उसके अनुसार यूपी में 80 लोकसभा सीटें जिसके अंतर्गत 403 विधान सभाएं आती हैं, वहां अबकी से बीजेपी 162 विधान सभा क्षेत्रों में समाजवादी और कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी से पिछड़ गई थी। इन 162 विधान सभा क्षेत्र के विधायकों पर भी गाज गिर सकती है।

वहीं 2027 में विपक्ष एक बार फिर से बेरोजगारी को मुद्दा नहीं बना पाये इसके लिये योगी ने सभी खाली पड़े रिक्त पदों को भरने के लिये बम्पर नौकरियां निकाली हैं। अभी एक लाख नौकरियां निकाले जाने की बात कही जा रही है जिसका आंकड़ा 2027 के विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आने तक पांच लाख तक पहुंच सकता हे। इसी के साथ पेपर लीक की घटनाओं पर अंकुश लगाने और इसमें लिप्त अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिये भी एसटीएफ तेजी से काम कर रही है। बेरोगारी और पेपर लीक की घटनाओं के चलते युवा वर्ग केन्द्र और राज्य सरकारों के खिलाफ काफी आक्रोशित है। उधर, इन युवाओं को गुस्से को विपक्ष हवा-पानी देने का काम कर रहा है। ऐसी ही एक मोदी सरकार की एक और योजना अग्निवीर भी सरकार के लिये बढ़ा मुद्दा बना हुआ है। विपक्ष लगातार इसे खत्म करने की मांग कर रहा है। इस योजना का दुष्प्रभाव मोदी सरकार लोकसभा चुनाव में देख भी चुकी है। कुल मिलाकर योगी सरकार बम्बर नौकरियां निकाल कर विपक्ष को उसकी बेरोजगारी वाली सियासत से 'बेरोजगार' करना चाहती है।

बात सरकार से हटकर संगठन स्तर की कि जाये तो लोकसभा चुनाव में यूपी से मिली चोट भाजपा को बेचैन किए हुए हैं। योगी की छवि पर भी प्रश्न चिन्ह लगा है। केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार के गठन के बाद भाजपा के जिम्मेदार अब यूपी में पार्टी के ग्राफ गिरने के कारणों की पड़ताल पर लगा है। पार्टी स्तर पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चैधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल ने वोट में आई गिरावट को लेकर चर्चा की। तय किया गया है कि भाजपा के पक्ष में कम मतदान की जांच होगी। दरअसल, यूपी के चुनाव परिणाम से भाजपा के स्थानीय से लेकर शीर्ष नेतृत्व में हड़कंप मचा हुआ है। पिछले चुनाव की तुलना में इस बार करीब नौ फीसदी कम वोट मिले हैं। अब इन्हीं वोट का पता लगाने को लेकर माथापच्ची शुरू हो गई है कि आखिर यह वोट भाजपा से छिटक कर कहां गया। इसका पता करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसमें संगठन के पदाधिकारियों के अलावा स्थानीय जनप्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। फोर्स के सदस्य गांव-गांव जाकर यह पता लगाएंगे कि भाजपा के कोर वोटर माने जाने वाले ओबीसी और दलितों में सेंध किस दल ने लगाया है।

यह भी पता लगाया जाएगा कि गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलितों को भाजपा से बिदकाने में किन-किन लोगों का हाथ है। साथ ही भितरघात करने वाले पार्टी नेताओं का भी पता किया जाएगा। केंद्र में भले ही लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बन गई है लेकिन पार्टी के लिए सबसे मजबूत सियासी जमीन यूपी में खिसकने की टीस सभी नेताओं को हो रही है। इसलिए अब पार्टी ने नुकसान पहुंचाने वालों के साथ उन मतदाताओं के बारे में भी पता लगाने का फैसला किया गया है कि जो इस बार भाजपा के बजाए विपक्ष की तरफ खिसक गए हैं। यूपी में बीजेपी का ग्राफ गिरने की पूरी समीक्षा के बाद यूपी बीजेपी में संगठन स्तर पर भी कई बदलाव हो सकते हैं। यूपी बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है और यह दलित अथवा पिछड़ा समाज को हो तो कोई आश्चर्य नहीं है। वैसे कयास यह भी लगाये जा रहे हैं कि योगी सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य एक बार फिर संगठन में आना चाह रहे हैं। मौर्य के यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रहते 2014 में पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था।

भाजपा इस बात को लेकर बेहद चिंतित है कि वर्ष 2017 में रिकॉर्ड 312 विधानसभा सीटों और 2022 के विधान सभा चुनाव में भी भगवा परचम लहराकर बहुमत की सरकार बनाने वाली भाजपा अबकी लोकसभा चुनाव में 162 सीटों पर ही कैसे पिछड़ गई। वहीं 2017 में कांग्रेस से हाथ मिलाने पर भी 47 सीटों पर सिमटकर सत्ता गंवाने वाली सपा इस चुनाव में सर्वाधिक 183 सीटों पर आगे रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में सिर्फ दो विधायक वाली पार्टी बनी कांग्रेस, लोकसभा चुनाव में सपा से गठबंधन कर 40 विधानसभा सीटों पर अव्वल आई। वैसे सच्चाई यह भी है कि 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद से यूपी में एनडीए का ग्राफ लगातार गिर रहा था, लेकिन इस ओर किसी ने विशेष ध्यान नहीं दिया। एनडीए के सहयोगी अपना दल (एस) व सुभासपा संग सरकार बनाने वाली भाजपा को पहला झटका 2019 के लोकसभा चुनाव में लगा। तब सपा-बसपा-रालोद के मिलने पर भाजपा के सांसद जहां 71 से घटकर 62 रह गए। वहीं पार्टी 274 विधानसभा सीटों पर ही बढ़त बना सकी थी। 2019 में सपा के पांच सांसद जीते और पार्टी 44 विधानसभा सीटों पर आगे रही थी, जबकि 10 सांसद वाली बसपा 66 विधानसभा सीटों पर आगे रही थी। सिर्फ रायबरेली लोकसभा सीट जीतने वाली कांग्रेस मात्र नौ सीटों पर ही औरों से आगे निकली थी। इसी तरह 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा यूपी में फिर सरकार बनाने में तो कामयाब रही, लेकिन उसकी सीटों और घट गई। भाजपा इस चुनाव में सिर्फ 255 सीटें ही हासिल कर सकी थी। रालोद व सुभासपा को साथ लेने से भी सपा पांच वर्ष बाद सरकार में वापसी तो नहीं कर सकी, लेकिन उसकी सीटें जरूर 47 से 111 हो गईं। सपा से हाथ मिलाने पर रालोद के आठ व सुभासपा के छह विधायक भी जीते। इसी तरह भाजपा के साथ रहने पर अपना दल (एस) के 12 विधान सभा उम्मीदवार जीते। अकेले चुनाव लड़ी कांग्रेस दो और बसपा एक ही सीट जीत सकी थी। यहां तक तो 'भगवा दल' के लिए किसी तरह के बड़े सियासी खतरे के संकेत नहीं थे, लेकिन इस लोकसभा चुनाव के आए नतीजे हर लिहाज से सत्ताधारी भाजपा के लिए खतरे की घंटी साबित हुए।

2024 लोकसभा चुनाव में घटते जनाधार के कारण भाजपा के जहां मात्र 33 सांसद रह गए है। वहीं विधानसभा सीटों पर भी दबदबा घट गया है। पिछले विधानसभा चुनाव में 255 सीटें जीतने वाली भाजपा को इस बार सिर्फ 162 सीटों पर ही बढ़त मिली है। सपा के साथ छोड़ फिर एनडीए के साथ आया रोलाद तो दो सांसदों के साथ आठ विधानसभा सीटों पर आगे रहा लेकिन एक सीट गंवाने वाला अपना दल (एस) सिर्फ चार विधानसभा क्षेत्रों में ही आगे है। सपा के अबकी कांग्रेस से हाथ मिलाने पर 37 सांसद तो जीते ही, उसे सर्वाधिक 183 विधानसभा सीटों पर बढ़त भी मिली है। यही वजह है कि दोनों ही पार्टियों के नेता न केवल उपचुनाव बल्कि अगला विधानसभा चुनाव भी साथ-साथ लड़ने की बात कहे रहे है।

कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव में भाजपा के एनडीए और कांग्रेस-सपा के आइएनडीआइए के बीच हुई लड़ाई को अगर विधानसभावार देखा जाए तो विपक्षी गठबंधन, सत्ताधारी एनडीए पर बहुत भारी दिखता है। एनडीए को जहां 174 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त मिली वहीं विपक्षी गठबंधन 224 सीटों पर आगे रहा है। 50 सीटों पर आगे रहना वाला विपक्षी गठबंधन, राज्य में सरकार बनाने के लिए जरूरी 202 सीटों के जादुई आंकड़े से कहीं अधिक है। इसी चिंता से मोदी-योगी और बीजेपी मुक्ति चाहते हैं।

योगी लगातार भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों में जोश भरने का काम कर रहे योगी अपने कार्यकर्ताओं को समझा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में विरोधियों के दुष्प्रचार और भ्रम जाल में फंसकर कई वोटर भाजपा से दूर चले गये थे, जिनको वापस अपने पाले में लाना होगा। मुख्यमंत्री ने बूथ स्तरीय पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपते हुए कहा कि रूठे लोगों के मनाएं और उन्हें दोबारा भाजपा के साथ मजबूतों से जोड़ें। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बूथ प्रभारी अपने-अपने बूथ पर मिले वोटों की समीक्षा करें। 2017 और 2022 के विधानसभा और 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में मिले वोटों के आधार पर नए सिरे से रणनीति बनाकर 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में अभी से जुट जाएं। स्वयं समीक्षा करें कि वोटों का अंतर क्यों कम हुआ है। जो कारण मिले उसे दूर करने की दिशा में काम करें।

– :सौजन्य :–
ईवी ड्राइव द फ्यूचर
EV Drive the Future

ठुकराल इलेक्ट्रिक बाइक्स ब्रांड ने ग्रीन व्हीकल एक्सपो में बिखेरा जलवा, पेश की फ्यूचरिस्टिक लुक वाली नई इलेक्ट्रिक ऑटो

परिवहन विशेष न्यूज

ठुकराल इलेक्ट्रिक बाइक्स ने ग्रीन व्हीकल एक्सपो 2024 में ग्रीन मोबिलिटी पर ध्यान केंद्रित करते हुए इलेक्ट्रिक ऑटो उत्पाद और तकनीकें पेश की हैं। कंपनी का मानना है कि दक्षिण भारत में इलेक्ट्रिक ऑटो में बदलाव हमारी कल्पना से कहीं ज़्यादा तेज़ी से होगा। उन्होंने कहा कि ठुकराल इलेक्ट्रिक बाइक्स के पास ग्राहकों की बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कई उत्पाद हैं।

कंपनी ने कहा कि हम अपने इलेक्ट्रिक ऑटो के महत्वपूर्ण अंदरूनी और बाहरी हिस्सों में हर तरह से डिजाइन के लिए प्रतिबद्ध हैं ताकि हम न केवल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में परिवर्तन को गति दे सकें बल्कि उपभोक्ताओं को विश्व स्तरीय उत्पाद भी दे सकें।

नोएडा में ई-वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन शुरू, 40 मिनट में फुल हो जाएगी बैटरी

परिवहन विशेष न्यूज

नोएडा। नोएडा के सेक्टर 15ए में रजनी गंधा मार्केट के पास दो नए इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया। नोएडा प्राधिकरण के जन स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ परियोजना अभियंता गौरव बंसल और ऑयल इंडिया लिमिटेड के निदेशक अशोक दास ने इन चार्जिंग स्टेशनों का उद्घाटन किया। यह सुविधा खास तौर पर इस सेक्टर के निवासियों के लिए फायदेमंद होगी, जो अब अपने इलेक्ट्रिक वाहनों को आसानी से चार्ज कर सकेंगे।

यह पहल नोएडा प्राधिकरण और एनजीओ गाइडेड फॉर्चून सोसाइटी के सहयोग से संभव हुई है, जहां ऑयल इंडिया लिमिटेड की बड़ी जमीन है। इस अवसर पर गाइडेड फॉर्चून सोसाइटी ने एक नई पहल की शुरुआत की। उन्होंने 'ट्रैशटॉक एक्टिविटी बुक' प्रकाशित की, जिसमें घरेलू स्तर पर कचरा प्रबंधन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। यह पुस्तक लोगों को उनके घरों में उचित कचरा प्रबंधन की विधि सिखाएगी, जो पर्यावरण संरक्षण में एक महत्वपूर्ण कदम है।

बिना रजिस्ट्रेशन वाले ई-रिक्शा को माना जाएगा जुगाड़ वाहन, पकड़े जाने पर कर दिया जाएगा कटवाकर नष्ट

परिवहन विशेष न्यूज

उत्तर प्रदेश के कासगंज में अपंजीकृत ई-रिक्शा पर लगाम लगाने के लिए विभाग ने तैयारी कर ली है। परिवहन विभाग में पंजीकृत न होने वाले ई-रिक्शा को जुगाड़ की श्रेणी में रखा जाएगा। ऐसे ई-रिक्शा को कटवा कर नष्ट कर दिया जाएगा। जिले में करीब 5000 ई-रिक्शा चल रहे हैं। इनमें से करीब 1280 ई-रिक्शा ही पंजीकृत हैं। एआरटीओ राम प्रकाश मिश्रा ने बताया कि जिले में करीब पांच हजार ई-रिक्शा चल रहे हैं। इनमें बड़ी संख्या में अपंजीकृत ई-रिक्शा हैं। पुराने ई-रिक्शा जर्जर हो चुके हैं।

ईवी दुनिया के सबसे बड़े एक्सपो में टाइटल पार्टनर का स्वागत

ईवीएक्सपो हर साल की तरह इस बार भी साल के अंत 2024 में एक्सपो लगाने की तैयारी में लगा हुआ है। यह एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहां आपको नई प्रौद्योगिकी और तकनीकी की जानकारी प्राप्त होती है। ईवीएक्सपो ना सिर्फ़ जानकारी प्रदान करता है अपितु व्यापार की नई योजनाओं को परिलक्षित करने का भी काम करता है। इसके तहत खालसा ईवी ने इलेक्ट्रिक वाहनों के दर्शकों तक अपनी रणनीतिक पहुंच को व्यापक बनाने के लिए ईवीएक्सपो के साथ करार किया है। इसे दिसंबर 2024 को भारत मंडपम, प्रगति मैदान, दिल्ली में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिए शीर्षक प्रायोजक के रूप में नामित किया गया है।

बारिश के मौसम में अपने इलेक्ट्रिक दो पहिया की करें सुरक्षा

परिवहन विशेष न्यूज

बरसात के मौसम में अपने इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन की देखभाल करना उसकी लंबी उम्र और बेस्ट परफॉर्मेंस सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। बारिश इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कई चुनौतियाँ पैदा करती है, लेकिन बारिश के मौसम में उचित रखरखाव के साथ आप अपने इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन की देखभाल के लिए संभावित समस्याओं को कम कर सकते हैं।

01. मानसून के मौसम में सड़कें फिसलन भरी होती हैं और ट्रैक्शन कम होता है, जिससे यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपके इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर की ब्रेकिंग प्रणाली अच्छी स्थिति में हो।

ब्रेक पैड, डिस्क और केबल का निरीक्षण करने के लिए कुछ समय निकालें। यदि आपको कोई घिसाव या कम प्रतिक्रिया के लक्षण दिखाई देते हैं, तो उन्हें जाँच लें और यदि आवश्यक हो तो बदल दें। अपने ब्रेक के अच्छे प्रदर्शन पर भरोसा करने से आपको गीली सवारी के दौरान मन की शांति मिलती है।

02. सुरक्षित सवारी के लिए अच्छी दृश्यता आवश्यक है, खासकर बरसात की स्थिति में। अपने इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर के सभी डीसी सर्किट का निरीक्षण करने के लिए समय निकालें, जिसमें हेडलाइट्स, टेल लाइट्स और इंडिकेटर्स शामिल हैं।

सुनिश्चित करें कि वे ठीक से काम कर रहे हैं और पर्याप्त रोशनी दे रहे हैं। यदि आपको कोई मंद रोशनी या टिमटिमाते संकेतक दिखाई देते हैं, तो बल्ब बदलने या वायरिंग कनेक्शन की जाँच करने का समय आ गया है।

03. जहां फेंडर कीचड़ और पानी के छींटों को कम करने में मदद करते हैं, वहीं मड फ्लैप्स लगाने से सुरक्षा एक कदम आगे बढ़ जाती है।

मड फ्लैप सरल लेकिन प्रभावी एक्सेसरीज हैं जो आपके इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर की बॉडी पर पानी और मलबे को गिरने से रोकते हैं, इसे साफ रखते हैं और जंग लगने की संभावना को कम करते हैं। इसलिए, मानसून के दौरान, इष्टतम सुरक्षा के लिए आगे और पीछे दोनों मडगार्ड पर मड फ्लैप लगाना उचित है।

04. मानसून के मौसम में अपने इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर की बैटरी चार्ज करने से पहले सुनिश्चित करें कि चार्जिंग क्षेत्र और बैटरी टर्मिनल सूखे हों। नमी से इलेक्ट्रिकल समस्याएँ हो सकती हैं और बैटरी को नुकसान पहुँच सकता है।

इसके अतिरिक्त, चार्ज करते समय, चार्जर पर किसी भी प्रकार की खराबी या अधिक गर्म होने के संकेतों की निगरानी करना तथा सुरक्षित और कुशल चार्जिंग प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतना उचित है।

05. गीली सड़कें बहुत फिसलन भरी हो सकती हैं, जिससे आपकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। सावधानी बरतें और अत्यधिक पानी या कीचड़ वाली सतहों पर गाड़ी चलाने से बचें।

ऐसी परिस्थितियाँ आपके वाहन की पकड़ और नियंत्रण को कम कर सकती हैं, जिससे मोड़ और अचानक पैंतरेबाज़ी करना मुश्किल हो जाता है। वैकल्पिक मार्ग चुनकर या सड़क की स्थिति में सुधार होने तक प्रतीक्षा करके सुरक्षित रहें।

06. आपके इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर के टायर सड़क के सीधे संपर्क में होते हैं, जिससे स्थिरता और नियंत्रण बनाए रखने के लिए वे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। टायर की स्थिति की नियमित रूप से जाँच करें, घिसाव, कट या उभार के संकेतों की जाँच करें।

अगर आपको टायर पंचर नज़र आए, तो उसे नया टायर लगवा लें। इसके अलावा, टायर के प्रेशर को नियमित रूप से जांचना न भूलें, क्योंकि सही हवा भरने से ट्रैक्शन बढ़ता है और यात्रा आरामदायक होती है।

07. आपके इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर का क्लस्टर एरिया, जिसमें इंस्ट्रूमेंट पैनल शामिल है, पानी से होने वाले नुकसान के प्रति संवेदनशील है। किसी भी समस्या को रोकने के लिए, सुनिश्चित करें कि क्लस्टर एरिया बारिश से अच्छी तरह सुरक्षित है।

आप महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को पानी से दूर रखने के लिए पारदर्शी कवर या शील्ड का उपयोग कर सकते हैं। यह सरल कदम आपको संभावित खराबी या क्षति से बचा सकता है।

08. बरसात में अपनी सवारी जारी रखते हुए आप अब सड़क पर आगे बढ़ रहे हैं, और आगे एक बड़ा सा गड्ढा है। आपका आंतरिक बच्चा आपको डुबकी लगाने के लिए प्रेरित कर सकता है, लेकिन एक जिम्मेदार ई-बाइक सवार के रूप में, प्रलोभन का विरोध करना सबसे अच्छा है।

हालाँकि इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर पानी प्रतिरोधी होते हैं, लेकिन गहरे पानी में गाड़ी चलाने से बचना बुद्धिमानी है, क्योंकि लंबे समय तक पानी के संपर्क में रहना, खास तौर पर गहरे गड्ढों में, आपके वाहन के संवेदनशील घटकों के लिए जोखिम पैदा कर सकता है।

इसके अलावा, ये दिखने में मासूम से दिखने वाले पोखर और पानी से भरे गड्ढे छिपे हुए खतरे हो सकते हैं जो आपकी सवारी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए, सावधान रहें, पानी वाली बाधाओं से दूर रहें और अपने इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर को सुरक्षित और स्वस्थ रखें।

09. अपनी ई-बाइक की लंबी उम्र बढ़ाने के लिए उचित चार्जिंग बेहद ज़रूरी है और मानसून के दौरान, यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि आप इस बात का ध्यान रखें कि आप अपनी ई-बाइक की बैटरी को कैसे और कब चार्ज करते हैं।

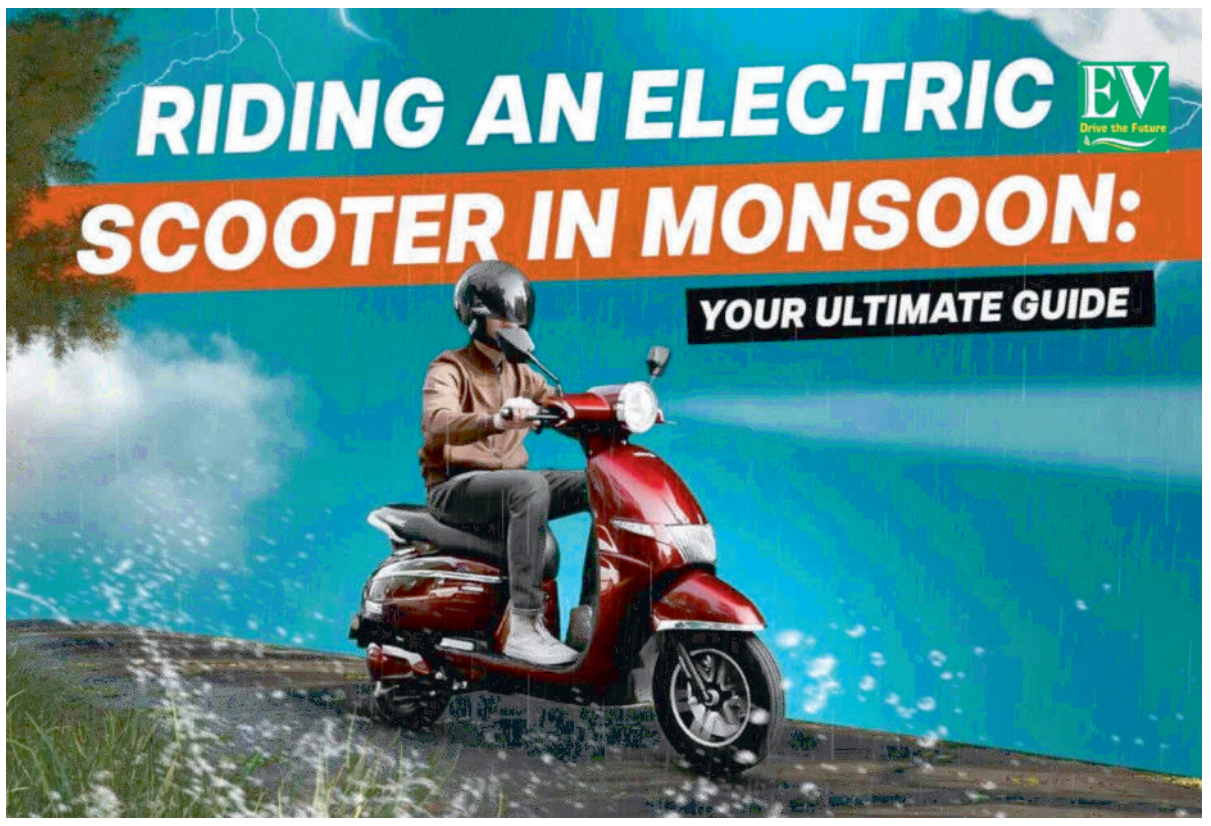

आंधी या भारी बारिश के दौरान, बिजली के उतार-चढ़ाव से होने वाले संभावित नुकसान को रोकने के लिए अपनी ई-बाइक की बैटरी को चार्ज करने से बचें। हालाँकि बैटरी वाहन के भीतर सीलबंद होती है, लेकिन पानी के प्रवेश और बैटरी को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए गहरे गड्ढों या पानी से भरे गड्ढों से गाड़ी चलाने से बचना सबसे अच्छा है।

10. हम सभी ने फिल्मों में ऐसे दृश्य देखे हैं जहाँ लोग अपने भीगे हुए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को चावल में सुखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब बात आपके इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर की बैटरी की आती है, तो चावल ज़्यादा मदद नहीं करेगा। अपनी ई-बाइक की बैटरी को अच्छी स्थिति में रखने के लिए, पानी के सीधे संपर्क से बचना ज़रूरी है।

हालाँकि बैटरी आपकी ई-बाइक के शरीर के अंदर सुरक्षित रूप से सील की गई है, लेकिन गहरे पानी में गाड़ी चलाने या पोखरों में छींटे मारने से बैटरी डिब्बे में पानी घुस सकता है। इससे संभावित रूप से नुकसान हो सकता है और आपकी मौज-मस्ती में बाधा आ सकती है। इसलिए, याद रखें, पानी और बैटरी एक-दूसरे के साथ अच्छी तरह से नहीं मिलते हैं। उन्हें सूखा रखें और चिंता मुक्त सवारी का आनंद लें।

> बरसात में अपनी सवारी जारी रखते हुए आप अब सड़क पर आगे बढ़ रहे हैं, और आगे एक बड़ा सा गड्ढा है। आपका आंतरिक बच्चा आपको डुबकी लगाने के लिए प्रेरित कर सकता है, लेकिन एक जिम्मेदार ई-बाइक सवार के रूप में, प्रलोभन का विरोध करना सबसे अच्छा है। हालाँकि इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर पानी प्रतिरोधी होते हैं, लेकिन गहरे पानी में गाड़ी चलाने से बचना बुद्धिमानी है, क्योंकि लंबे समय तक पानी के संपर्क में रहना, खास तौर पर गहरे गड्ढों में, आपके वाहन के संवेदनशील घटकों के लिए जोखिम पैदा कर सकता है। इसके अलावा, ये दिखने में मासूम से दिखने वाले पोखर और पानी से भरे गड्ढे छिपे हुए खतरे हो सकते हैं जो आपकी सवारी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए, सावधान रहें, पानी वाली बाधाओं से दूर रहें और अपने इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर को सुरक्षित और स्वस्थ रखें।

11. अपनी ई-बाइक पर बरसात के रोमांच के बाद, अब उसे ताज़ा करने का समय आ गया है, तो एक बाल्टी, कुछ हल्का डिटर्जेंट लें, और सफाई शुरू करें। अपने वाहन के शरीर को धोने से शुरू करें, मानसून की छुट्टियों के दौरान जमा हुई किसी भी कीचड़ या गंदगी को हटा दें।

अंडरकैरिज, पहियों और फेंडर पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि इन क्षेत्रों में सबसे अधिक गंदगी जमा होती है। एक बार जब आप काम पूरा कर लें, तो यह सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि आपका इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर पूरी तरह से सूखा हो। एक साफ कपड़ा या तौलिया लें और इसे अच्छी तरह से पोंछ लें। यह कीचड़ और नमी को जमा होने से रोकता है, जिससे जंग लगने और संभावित नुकसान की संभावना कम हो जाती है।

12. आप अपनी इलेक्ट्रिक बाइक पर लंबी सवारी से अभी-अभी लौटे हैं और बारिश शुरू हो जाती है। आप जल्दी से अपनी गाड़ी बाहर पार्क करते हैं, ताकि मौसम की मार से बच सकें और घर के अंदर भागते हैं। लेकिन रुकिए, बारिश के प्रकोप से अपनी ईवी को बचाने का एक बेहतर तरीका है।

अगर संभव हो तो, ढकी हुई पार्किंग जगह चुनें। चाहे वह गैरेज हो, कारपोर्ट हो या कोई निर्धारित पार्किंग क्षेत्र हो, अपनी इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर के लिए आश्रय ढूँढना चमत्कार कर सकता है।

इसे बारिश के सीधे संपर्क से बचाकर, आप पानी के नुकसान के जोखिम को कम करते हैं और अपने वाहन की समग्र स्थिति को बनाए रखते हैं। इसलिए, अगली बार जब आप अपनी पार्किंग रणनीति की योजना बनाते हैं, तो कवर के बारे में सोचें और अपनी ई-बाइक को वह आश्रय दें जिसकी वह हकदार है।

13. आप सोच रहे होंगे, क्या होगा अगर मेरे पास ढकी हुई पार्किंग तक पहुंच न हो? कोई बात नहीं! अपनी ई-बाइक की बैटरी को सुरक्षित रखने का एक सरल और प्रभावी तरीका अभी भी है इसे घर के अंदर ले आएं। भारी बारिश या लंबे समय तक निष्क्रियता के दौरान, बैटरी को अपने साथ घर के अंदर ले जाने पर विचार करें।

इसे नमी और गीले वातावरण से दूर रखकर, आप संभावित जल क्षति के खिलाफ सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत जोड़ते हैं। इसलिए, अपने ईवी की बैटरी के लिए घर के अंदर एक सूखी जगह ढूंढें, चाहे वह आपका गैरेज हो, स्टोररूम हो या फिर आपका लिविंग रूम (जब तक वह सुरक्षित और सूखा हो)। आपकी बैटरी अतिरिक्त देखभाल के लिए आपको धन्यवाद देगी!

14. आपकी ईवी धूप और बारिश में आपका भरोसेमंद साथी रही है, लेकिन इसे कुछ पेशेवर ध्यान देना हमेशा एक अच्छा विचार है। मानसून के मौसम से पहले और बाद में, अपने इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर के लिए एक योग्य तकनीशियन या सर्विस सेंटर से चेक-अप शेड्यूल करने पर विचार करें।

इन जांचों के दौरान, विशेषज्ञ आपके वाहन का गहन निरीक्षण कर सकते हैं, किसी भी संभावित समस्या की पहचान कर सकते हैं और आवश्यक रखरखाव कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि आपकी ई-बाइक इष्टतम स्थिति में है, जिससे बारिश के मौसम में अप्रत्याशित खराबी का जोखिम कम हो जाता है।

मानसून के मौसम में इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर चलाना डर का विषय नहीं है। इन विस्तृत सुझावों का पालन करके आप अपनी ई-बाइक की देखभाल कर सकते हैं, जिससे बारिश की स्थिति में इसकी लंबी उम्र और बेहतरीन प्रदर्शन सुनिश्चित हो सके।

तो, तैयार हो जाइए, बारिश का मज़ा लीजिए और अपने अच्छी तरह से बनाए रखे गए और भरोसेमंद इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर के साथ मानसून के डर पर विजय पाइए। किसी भी मौसम में सवारी करने का आनंद लें।

ऐतिहासिक नए बजट की उम्मीद

डा. जयंती लाल भंडारी

इन दिनों पूरे देश की निगाहें 23 जुलाई को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किए जाने वाले वर्ष 2024-25 के पूर्ण बजट की ओर लगी हुई हैं। उम्मीद की जा रही है कि यह बजट विकास और सुधारों से सजा हुआ ऐतिहासिक बजट होगा।

टीडीएस के कारण वेतनभोगी अपने वेतन पर ईमानदारीपूर्वक आयकर चुकाते हैं और आमदनी को कम बताने की गुंजाइश नगण्य होती है। ऐसे में टीडीएस की वर्तमान 50000 रुपए की सीमा को बढ़ाकर 75000 रुपए किया जा सकता है। हम उम्मीद करें कि 23 जुलाई को वित्तमंत्री सीतारमण के द्वारा पेश होने वाला वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट आर्थिक सुधारों, आर्थिक कल्याण और तेज विकास के आधारों को आगे बढ़ाने वाला ऐतिहासिक बजट होगा। यह एक ऐसा बजट भी होगा, जिसमें वित्तमंत्री राजकोषीय घाटे को 2025-26 में 4.5 फीसदी तक लाने का लक्ष्य आगे बढ़ाते हुए दिखाई देंगी'

इन दिनों पूरे देश की निगाहें 23 जुलाई को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किए जाने वाले वर्ष 2024-25 के पूर्ण बजट की ओर लगी हुई हैं। उम्मीद की जा रही है कि यह बजट विकास और सुधारों से सजा हुआ ऐतिहासिक बजट होगा। इस बजट को तैयार करने के मद्देनजर वित्तमंत्री सीतारमण ने 19 जून से 5 जुलाई तक उद्योग-कारोबार, श्रम, कृषि, एमएसएमई, टैक्सेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य, उपभोक्ता, आधारभूत ढांचा, वित्त क्षेत्र सहित बजट से संबंधित विभिन्न पक्षों के साथ बजट पूर्व व्यापक परामर्श बैठकें आयोजित की हैं। गौरतलब है कि गत 27 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार के तीसरे कार्यकाल में वर्ष 2024-25 का बजट ऐतिहासिक होगा और इसमें आर्थिक तथा सामाजिक मोर्चे पर बड़े ऐलान किए जाएंगे। इस बजट से सरकार सुधारों की प्रक्रिया को और तेज करेगी। यह बजट नई गठबंधन सरकार की नीतियों और भविष्य के दृष्टिकोण के लिहाज से बहुत ही प्रभावी दस्तावेज होगा। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि देश में विभिन्न सुधारों से भारतीय बैंकिंग विश्व के सबसे मजबूत बैंकिंग क्षेत्रों में शुमार हो गई है। टैक्स संग्रहण ऊंचाई पर है। गरीब, युवा, महिलाएं और किसानों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों से इन वर्गों का उत्थान हुआ है। मुर्मू ने कहा कि पिछले दस वर्षों में सरकार के मंत्र रिफॉर्म, परफॉर्म ऐंड ट्रांसफॉर्म ने भारत को विश्व की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था बनाया है और भारत ने 2021 से 2024 के बीच आठ प्रतिशत सालाना की दर से वृद्धि की है।

उन्होंने कहा कि नए बजट के माध्यम से अटके पड़े सुधारों, वित्तीय व श्रम सुधारों को आगे बढ़ाया जाएगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, उद्योग जगत की लाजिस्टिक्स लागत घटाने, वैश्विक बाजार में भारतीय खाद्यान्नों की मांग बढ़ाने, किसानों की आय बढ़ाने तथा रोजगार सृजित करने वाले मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर पर फोकस करने के बड़े कदम आगे बढ़ाए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि इसी वर्ष एक फरवरी को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया वर्ष 2024-25 का अंतरिम बजट एक लेखानुदान की तरह था तथा इसमें कोई लोक लुभावन योजना नहीं थी। ऐसे में इस अंतरिम बजट ने 23 जुलाई को प्रस्तुत किए जाने वाले वर्ष 2024-25 के पूर्ण बजट के लिए अच्छे आर्थिक और वित्तीय आधारों की विरासत सौंपी है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि पूर्ण बजट 2024-25 की तैयारी को अंतिम रूप देते समय वित्तमंत्री सीतारमण के पास अच्छे व ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत करने के कई मजबूत आधार हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा वित्त मंत्रालय को 2.11 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम लाभांश सौंपा गया है, वह भी नए बजट का मजबूत आधार होगा। इस लाभांश से सरकार को राजकोषीय सहायता मिलेगी और व्यय अपेक्षाओं का प्रबंधन होगा। आयकर परिदृश्य पर सकारात्मक बदलाव होने का अनुकूल परिदृश्य मौजूद है। पिछले 10 वर्षों में आयकर रिटर्न भरने वाले आयकरदाताओं की संख्या और आयकर की प्राप्ति में छलांगे लगाकर वृद्धि हुई है। आयकर रिटर्न रिकॉर्ड आठ करोड़ के स्तर को पार कर चुका है। जहां पिछले 10 वर्षों में आयकर रिटर्न भरने वाले दोगुने से भी अधिक हुए हैं, वहीं आय की असमानता में भी कमी आई है। वित्तमंत्री की मुट्ठियों में देश में कर सुधारों से आयकरदाताओं और आयकर संग्रहण के साथ-साथ जीएसटी में लक्ष्य से भी अधिक वृद्धि की बड़ी अनुकूलताएं हैं।

इसके अलावा पिछले वर्षों में वित्तमंत्री सीतारमण वित्तीय अनुशासन का पालन करते हुए अब तक राजकोषीय घाटे को बजट लक्ष्य के मुताबिक उपयुक्त रूप से नियंत्रित रखते हुए सफलतापूर्वक आगे बढ़ी हैं। निःसंदेह नया बजट 2024-25 गरीब, युवा, महिलाएं और किसानों के कल्याण के नए उपायों के साथ विकास योजनाओं पर केंद्रित होते हुए दिखाई दे सकता है। नए बजट में वित्तमंत्री वृद्धि और रोजगार पर फोकस करते हुए दिखाई दे सकती हैं। किसान सम्मान निधि सालाना 6000 रुपए से बढ़ाकर 8000 रुपए की जा सकती है। कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई, वेयरहाउसिंग को प्रोत्साहन नए बजट में बढ़ाए जा सकते हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) को प्रोत्साहनमूलक राहत दी जा सकती है। जहां विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी करने के लिए सरकार नए बजट से पीएलआई योजना का दायरा बढ़ाते हुए इसे नए क्षेत्रों तक विस्तृत कर सकती है और श्रम साध्य क्षेत्रों में नई नौकरियों के सृजन के पथ पर आगे बढ़ सकती है, वहीं रियल एस्टेट सेक्टर और आवास सेक्टर को भी प्रोत्साहनमूलक राहत दे सकती है। नए बजट में देश में डिजिटल क्रांति को बढ़ाने से संबंधित मोबाइल सेवा प्रदाताओं सहित विभिन्न उत्पादों, बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए अधिक पूंजीगत व्यय के प्रावधान भी दिखाई दे सकते हैं। उल्लेखनीय है कि इन दिनों वेतनभोगी (सेलरीड) वर्ग के लाखों छोटे आयकरदाता और मध्यम वर्ग के लोग यह कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि पिछले विभिन्न बजटों में उन्हें टैक्स संबंधी कोई उपयुक्त राहत नहीं मिली है। साथ ही अब महंगाई वृद्धि और उनके बढ़ते जरूरी खर्चों के कारण उन्हें कुछ आयकर राहत की अपेक्षा है। वित्तमंत्री नए बजट में खपत को बढ़ावा देने के लिए 50 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा के उपाय भी कर सकती हैं, जिसमें कर राहत के उपाय भी शामिल हैं। ऐसे में नए बजट में आयकर के पुराने तथा नए स्लैब दोनों के तहत छोटे आयकरदाताओं को राहत के प्रावधानों का ऐलान किया जा सकता है। निःसंदेह वेतनभोगी वर्ग के द्वारा नए बजट में राहत की अपेक्षा इसलिए भी न्यायसंगत है, क्योंकि वेतनभोगी वर्ग के द्वारा दिया गया कुल आयकर पेशेवरों और कारोबारी करदाताओं के वर्ग द्वारा चुकाए गए कुल आयकर से काफी अधिक होता है।

वेतनभोगी वर्ग के करदाताओं के कर की कटौती आमदनी अर्जित करने के स्रोत पर अर्जित आय पर की जाती है। इसे टीडीएस के रूप में जाना जाता है। टीडीएस के कारण वेतनभोगी नियमानुसार अपने वेतन पर ईमानदारीपूर्वक आयकर चुकाते हैं और आमदनी को कम बताने की गुंजाइश नगण्य होती है। ऐसे में टीडीएस की वर्तमान 50000 रुपए की सीमा को बढ़ाकर 75000 रुपए किया जा सकता है। हम उम्मीद करें कि 23 जुलाई को वित्तमंत्री सीतारमण के द्वारा पेश होने वाला वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट आर्थिक सुधारों, आर्थिक कल्याण और तेज विकास के आधारों को आगे बढ़ाने वाला एक ऐतिहासिक बजट होगा। यह एक ऐसा बजट भी होगा, जिसमें वित्तमंत्री 2024-25 के तहत राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 5.1 फीसदी और 2025-26 में 4.5 फीसदी तक लाने का लक्ष्य आगे बढ़ाते हुए दिखाई देंगी। साथ ही वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट भारत को 2027 तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था तथा वर्ष 2047 तक भारत को दुनिया का विकसित देश बनने के सपने को साकार करने की डगर पर आगे बढ़ाने वाला बजट भी होगा।

संपादक की कलम से

दबाव में प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में अधिक दबाव और तनाव में रहेंगे। बुनियादी कारण यह है कि भाजपा के पक्ष में सामान्य बहुमत नहीं है, लिहाजा गठबंधन का सहारा लेना पड़ा है। पहले दो कार्यकालों में अकेली भाजपा को लबालब बहुमत हासिल था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए को बरकरार रखा और कैबिनेट में भी स्थान दिया था। अब स्थितियां ऐसी नहीं हैं कि प्रधानमंत्री के करिश्मे और प्रभाव से ही सब कुछ संचालित होता रहे। चुनाव लडना और जीतना 'बायें हाथ का खेल' समझा जाए। बेशक देश के 20 से अधिक राज्यों और केंद्रशासित क्षेत्रों में भाजपा-एनडीए की सरकारें हैं। संसद के दोनों सदनों में सर्वाधिक सांसद हैं। विधायक भी सबसे अधिक हैं। इनके बावजूद प्रधानमंत्री का दबाव और तनाव में रहना तार्किक न लगे, लेकिन हालात ऐसे ही बनते जा रहे हैं। सबसे पहले तेलुगूदेशम पार्टी (टीडीपी) को ही लें, जिसके 16 लोकसभा सांसदों का समर्थन मोदी सरकार के स्थायित्व के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। टीडीपी अध्यक्ष एवं आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू बीते दिनों दिल्ली प्रवास पर थे। उन्होंने सरकार से एक लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज तुरंत मांगा था। उसमें से 50,000 करोड़ रुपए उन्हें अविलंब चाहिए थे, क्योंकि आंध्र की नई राजधानी अमरावती और दूसरे रूटीन के खर्चों के लिए उन्हें धन की आवश्यकता थी। आंध्र भारी कर्ज के बोझ तले दबा है। चंद्रबाबू की इस मांग पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने असमर्थता जताई कि इतने अतिरिक्त धन की व्यवस्था देखनी पड़ेगी। नायडू ने प्रधानमंत्री से मिल कर आग्रह किया कि एक कमेटी बनाई जाए, जिसकी अध्यक्षता उन्हें सौंपी जाए। चंद्रबाबू के ये तेवर ही मोदी सरकार पर दबावों की शुरुआत हैं।

बिहार में 'विशेष राज्य के दर्जे' की मांग मजबूत होती जा रही है। घटक दलों के नेताओं के बयान आ रहे हैं कि यह बिहार का बुनियादी अधिकार है। बिहार से जद-यू के 12 सांसद हैं। उन्हें भी जानकारी है कि यह दर्जा दिया जाना कानूनन संभव नहीं है, क्योंकि वित्त आयोग इस व्यवस्था को 2014 में ही निरस्त कर चुका है। बहरहाल गठबंधन में दरार, दरकने और टूटने के कोई आसार नहीं हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर गठबंधन में अलगाव आने लगता है, तो राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन कैसे और कब तक बरकरार रह सकता है? संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से शुरू हो रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को सदन में बजट पेश करेंगी। उसके मद्देनजर भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ और स्वदेशी जागरण मंच ने अपने-अपने मांग-पत्र वित्त मंत्री को सौंपे हैं। ये सभी संगठन आरएसएस के हैं, लिहाजा उनकी मांगों को यूं ही नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसे कई और भी संगठन होंगे, जो बजट में अपनी मांगों को पूरा कराना चाहते होंगे! इसके अलावा, राजनीति और चुनावों के अलग तनाव और दबाव हैं। आम चुनाव, 2024 से लेकर हालिया 13 उपचुनावों तक जनादेश 'भाजपाई' नहीं रहा है। लोकसभा में भाजपा के 63 सांसद पराजित हुए हैं और 10 उपचुनाव विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' के पक्ष में रहे हैं। भाजपा के हिस्से मात्र दो जीत ही आई हैं। अभी तो उप्र में कई सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसी अक्तूबर-नवंबर में हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे। भाजपा का वर्चस्व दांव पर है। अब लगता है कि ध्रुवीकरण, दलबदलुओं, हिंदुत्व, सांप्रदायिकता आदि से चुनाव जीते नहीं जा सकते। अब भाजपा को रणनीति बदलनी पड़ेगी। अब भाजपा को पूरी ताकत, दिमाग, विचारधारा और काडर के सहयोग से चुनाव लडने होंगे, तभी राजनीतिक हैसियत बरकरार रह सकती है। हालांकि जो चुनाव होने हैं, वे देश की सत्ता को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करेंगे।

ज्ञान

हारे तो हम-1

कितनी मिट्टी खोदी होगी, कितने अवसर दफन हुए होंगे, जब जनादेश के गणित में उपचुनावों की मंडी में हम, आप और हमारा संताप हाजिरी लगा रहा था। इस बार हिमाचल के उपचुनाव एक कड़वी दास्तान, महंगी सहूलियत और लोकतांत्रिक विडंबना माने जा सकते हैं। राजनीतिक जरूरतें कितनी बढ़ गईं कि एक साथ नौ विधानसभा क्षेत्रों में फिर से मतदाताओं की कतारें लग गईं। सवाल अनेक, दोष एक कि हमें मतदाता और बेशकीमती मत के बावजूद हार, हताशा और हतप्रभ होने के लिए राजनीतिक चरित्र हमेशा पहले से और भौंडा, अप्रीतिकर और असंगत हो गया। ये उपचुनाव कितने जमा व कितने के भ्रम में कहता, सुनाता और लोरियों के मौसम में हमारी चेतना सुलाता रहा। हम जागे नहीं, सोए-सोए वोट देते रहे, क्योंकि देश में चौथे ऐसे प्रदेश के बाशिंदे हैं जहां प्रतिव्यक्ति राज्य की उधारी बढ़ रही है। आखिर हिमाचल में उपचुनावों में 6 जमा तीन का फार्मूला था क्या और परिणामों में छह बनाम तीन हुआ क्यों। क्या सत्ता सशक्त हुई या राजनीतिक गुरूर बढ़ा। क्या विपक्ष ताकतवर हुआ या सियासी मुकाम मिट्टी में मिल गया। जो भी हो, होशियार सिंह, केएल ठाकुर, रवि ठाकुर, देवेंद्र भुट्टो, चैतन्य शर्मा और राजेंद्र राणा भले-चंगे विधायक होते, मगर शेखियों ने हिमाकत ऐसी की कि जमी जमाई दौलत व इज्जत लुट गई। कहना न होगा कि हिमाचल को उपचुनाव की न जिरह, न तर्क पसंद आए, वरना कल के नायक आज खलनायक न होते।

हिमाचल में कुछ सरमायेदारों ने राजनीति का वशीकरण किया, लेकिन इन उपचुनावों में सुजानपुर से राजेंद्र राणा और देहरा से होशियार सिंह का हारना उस दौलत और शोहरत का हारना भी है, जिसे इन दोनों ने अर्जित किया। अब परिणामों के पटाक्षेप में साढ़े तीन साल की सत्ता को ठीकठाक बहुमत और विपक्ष को सुनाने का पूर्ण हक मिल गया, जबकि तीन सीटें बढ़ाकर भी भाजपा के महल में कई चिराग गुल हैं। उपचुनावों में सारा वीर रस मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ले गए, क्योंकि उनकी सरकार और उनका परिवार लाभान्वित है। कांग्रेस जितनी व जिस सूरत में उन्हें चाहिए थी, मिल गई। राज्यसभा चुनाव में खंजर चुभोने वाले अधिकांश चेहरे निपटाए जा चुके हैं, लेकिन सियासत के कई अर्थ उन्हें स्वीकार करने होंगे। हमीरपुर से आशीष शर्मा और इंद्रदत्त लखनपाल जीत कर विधानसभा में लौट रहे हैं। तीन ऐसे विधायक लौट रहे हैं जो कल तक कांग्रेस की बोली और कांग्रेस की हां में हां मिलाते थे। शोर अब इतना न बढ़ जाए कि जनता की नींद हराम होने लगे। रोष इतना न बढ़ जाए कि हिमाचल लोकसभा बनाम विधानसभा में बंट जाए। आर्थिक चुनौतियों के बीच पिछले चुनावों के बाद लोकसभा से उपचुनावों तक कांग्रेस के वादे बढ़ गए हैं। हर चुनाव शेखचिल्ली होता है। पिछले ने गारंटियों की माला पहनाई थी, तो उपचुनावों ने आरती उतारी है। यहां रिश्तों की दुहाई, मायके की कमाई और दलबदलुओं की लड़ाई थी, इसलिए जनता ने इंतखाब किया या बदला लिया, लेकिन अब विकास के गहनों का मुकाबला विकास के घुंघरुओं से है। घुंघरू कहीं भी, कभी भी बज सकते हैं और बजते आए हैं, लेकिन विकास के मंचन में अब सरकार की बारी है। बहरहाल हिमाचल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि निर्दलीय पर उम्मीदें नहीं और यह भी कि तीसरी शक्ति के उदय से यहां राजनीतिक समाधान नहीं। देखना यह है कि उपचुनावों ने जो भी मुखौटे पहने, वे यथार्थ में आगे कैसे उतरते हैं और यह भी कि जो महीने आचार संहिता के बंधक बन कर उजड़ गए, वे लौटते हैं या नहीं। उपचुनावों के बाद सत्ता और विपक्ष के बीच आदतें बदलती हैं या बदलाव की जरूरतों में सियासत कितनी बदलती है, यह देखना होगा। – क्रमशः

टीबी उन्मूलन के लिए प्रयास और चुनौतियां

टीबी के मरीजों को नियमित चिकित्सा सेवाएं, दवाइयां और पोषण सहायता मिलनी चाहिए। इसके अलावा समाज को भी आगे आकर टीबी के रोगियों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार अपनाना चाहिए। इससे टीबी रोगियों में जो हीन और अलगाव की भावना उत्पन्न हुई होती है, उससे छुटकारा मिलेगा। टीबी उन्मूलन कार्यक्रम को सही मायने में अपनाने और प्रदेश व देश को टीबी मुक्त करने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है'

टीबी उन्मूलन के लिए पूरी दुनिया में प्रयासों में तेजी लाई जा रही है। भारत और हिमाचल प्रदेश में भी इससे छुटकारा पाने के लिए टीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जहां विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2030 तक दुनिया को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है, वहीं भारत ने 2025 तक टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य रखा है। भारत को टीबी मुक्त करने के लिए केंद्र, राज्य और स्वयं सहायता संगठनों द्वारा विभिन्न स्तरों पर कार्य किए जा रहे हैं। लेकिन इन कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार-प्रसार और लोगों तक पहुंच न होने के चलते भारत का 2025 तक टीबी मुक्त होना संभव नहीं लग रहा है। 2024 आधा गुजर चुका है और पूरी दुनिया के 26 फीसदी से अधिक टीबी के रोगी भारत में देखे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भारत में टीबी के मामले कम नहीं हो रहे, लेकिन टीबी मुक्त होने के लिए टीबी के मामलों में जिस गति से कमी आनी चाहिए, वह नहीं हो पा रही है। यही हाल पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी देखा जा रहा है। भले ही पिछले चार वर्षों में हिमाचल प्रदेश टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के आयोजन में पूरे देश में पहला स्थान हासिल कर रहा हो, लेकिन इसके बावजूद प्रदेश में हर साल लगभग 15 हजार टीबी के मामले देखे जा रहे हैं। साक्षरता में दूसरे स्थान पर रहने वाले हिमाचल प्रदेश में पर्याप्त जागरूकता न होने के चलते अभी भी टीबी के प्रति अंधविश्वास और भ्रांतियां कम नहीं हो पा रही हैं, जिससे टीबी को पूरी तरह खत्म करने में अनेकों चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

प्रदेश में पोषणयुक्त खाद्यान की कमी, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, जागरूकता की कमी, ग्रामीण क्षेत्रों में टेस्टिंग की सुविधा न होने के चलते टीबी हर साल पहाड़ के 1000 के करीब लोगों की जानें लील रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि टीबी का पोषणयुक्त आहार और लोगों के स्वास्थ्य के हालात के साथ सीधा संबंध है। जिन क्षेत्रों में पोषणयुक्त आहार मिलते हैं वहां पर लोगों के स्वास्थ्य के हालात अच्छे होते हैं और ऐसे क्षेत्रों में टीबी जैसे संक्रामक रोग का प्रसार अधिक नहीं देखा जाता है। जबकि पोषणयुक्त आहार न मिलने के चलते स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों से जूझने वाले क्षेत्रों में इस संक्रामक रोग का प्रसार अधिक देखा गया है। नेशनल फेमिली हेल्थ सर्वे-5 के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में 6 से 59 माह तक के 55 फीसदी बच्चों में एनीमिया, 53 फीसदी महिलाओं में भी एनीमिया, 15 से 49 वर्ष तक की 13.9 फीसदी महिलाओं का बॉडी मास इंडेक्स सामान्य से कम पाया गया। वहीं 30 फीसदी महिला और पुरुषों में मोटापे की समस्या पाई गई है। सर्वे में निकलकर आए यह आंकड़े न सिर्फ चौंकाने वाले हैं, बल्कि इन्हें देखते हुए समय रहते सतर्क होने की भी जरूरत है। लोगों के स्वास्थ्य हालात में सुधार के लिए पोषणयुक्त आहार की उपलब्धता के लिए सरकारों को प्रयासों में तेजी लानी चाहिए ताकि इनकी वजह से टीबी सहित अन्य बीमारियों से लडने के लिए लोगों में इम्यूनिटी तैयार हो सके। पोषण विशेषज्ञ के अनुसार टीबी के मरीजों को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और मिनरल्स से युक्त आहार लेना चाहिए। मांस, मछली, अंडे, दूध, दही, पनीर, फल और सब्जियां शामिल होने चाहिए। प्रोटीन की मात्रा 1.2 से 1.5 ग्राम प्रति किलोग्राम आइडियल बॉडी वेट के अनुसार होनी चाहिए। साथ ही विटामिन डी, ई, सी, ए और बी कॉम्प्लेक्स, सेलेनियम, जिंक, फोलिक एसिड और कैल्शियम का सेवन भी जरूरी होता है।

इसके अलावा टीबी के मरीजों को एंटीबायोटिक दवाओं के साथ-साथ मल्टी विटामिन, मल्टी मिनरल्स और पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर का सेवन करना चाहिए। संक्रमित व्यक्ति को सही वजन बनाए रखने के लिए सामान्य से 20-30 फीसदी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रदेश में कई लोगों के पास पर्याप्त पोषक तत्वों से युक्त खाद्यान तक पहुंच नहीं है। गरीबी, कृषि उत्पादकता में कमी और खाद्य वितरण प्रणाली की कमियों के कारण कई लोग पर्याप्त पोषण नहीं ले पा रहे हैं। पोषणयुक्त आहार की कमी से टीबी रोगियों का स्वास्थ्य और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित होती है। इससे उनकी बीमारी का इलाज और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करना कठिन हो जाता है। सरकार को गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को पोषक खाद्यान उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाने चाहिए। खाद्य वितरण प्रणाली में सुधार किया जाना चाहिए। टीबी के मरीजों को नियमित और पर्याप्त मात्रा में दवाएं और पोषक आहार उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार जरूरी है। इन उपायों से टीबी के प्रकोप को कम करने और मरीजों के स्वास्थ्य में सुधार लाया जा सकता है। सरकार, स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय समुदाय को मिलकर काम करना होगा। इसके अलावा हिमाचल में कई दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच नहीं है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की कमी है। टीबी के मरीजों को नियमित चिकित्सा सेवाएं, दवाइयां और पोषण सहायता मिलनी चाहिए। इसके अलावा समाज को भी आगे आकर टीबी के रोगियों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार अपनाना चाहिए। इससे टीबी रोगियों में जो हीन और अलगाव की भावना उत्पन्न हुई होती है, उससे छुटकारा मिलेगा। टीबी उन्मूलन कार्यक्रम को सही मायने में अपनाने और प्रदेश व देश को टीबी मुक्त करने के लिए सरकार, स्वास्थ्य कर्मियों, सामाजिक संगठनों और समाज को मिलकर काम करने के लिए आगे आना चाहिए। साथ ही टीबी के प्रति लोगों में वृहद जागरूकता कार्यक्रम चलाने की जरूरत है। इसके अलावा जो लोग टीबी से मुक्त हो रहे हैं, उन्हें आगे आकर इसके बारे में समाज में जागरूकता फैलाने के साथ इससे निपटने के बारे में विस्तार से जानकारी साझा करनी चाहिए।

रोहित पराशर

शव संवाद-52

पुतला तुरंत जलना चाहता था, लेकिन वे इसे पूरी शिद्दत से बचा रहे थे। पुतला खुद पर शर्मिंदा था, इसलिए पूरी तरह जल जाना चाहता था, मगर इसे बचाने वालों को भली-भांति मालूम था कि यह किसका अवतार है। जल गया तो देश को मालूम हो जाएगा कि किसकी वजह से बना और किसके कारण जला। पुतला मुर्दा नहीं था, लेकिन जलेगा तो कई जिंदा मुर्दा हो जाएंगे। पुतला खुद में ज्वलनशील नहीं है, फिर भी उसे किसी न किसी के लिए ही जलना पड़ता है। पुतला शाश्वत है। एक बार जलता, फिर पैदा हो जाता। पुतले के कद्रदान बढ़ रहे हैं, बल्कि पुतलों की वजह से नागरिक खुद में एक हस्ती हैं। पुतले का हर जगह शमशान है। मुख्य चौराहों, सरकार की सैरगाहों, सचिवालयों की बाहों और सदनों की निगाहों में आकर ही पुतला जलता है। पुतले की एक ही इच्छा है कि वह बार-बार देश की किसी न किसी नामचीन हस्ती के नाम पर मरे। इसलिए कितने ही मंत्री, मुख्यमंत्री और अब तो प्रधानमंत्री भी पुतला बनने के योग्य हो गए हैं, लेकिन वह चाहकर भी बुद्धिजीवी का पुतला नहीं बन सका। यह पुतला लोकतांत्रिक है और लोकतंत्र की रक्षा के संदर्भ में ही जलता है। इसकी सामग्री लोकतांत्रिक है। एक पुतला ही देश में बचा है, जिसे आम नागरिक बना सकता है, वरना देश में सबसे अधिक नागरिक समाज को ही बनाया जा रहा है। नागरिक अब पुतले बनाने लायक ही बचा है, इसलिए इसी कौशल से देश को प्रभावित करना चाहता है, वरना राजनीतिक नेताओं की करामात तो यह कि वे कब्रें खोद कर गढ़े मुर्दों से मुर्दा समाज को लड़ा रहे हैं।

खैर बुद्धिजीवी की सारी आस्था अब पुतले में है, इसलिए पुतलों के पास देश की संवेदनशील जनता पहुंच जाती है, वरना संसद में अब ऐसा नजारा है कहां। दरअसल बुद्धि का ताल्लुक नेता से नहीं, वक्त पर काम आए पुतले से हो गया है। संसार में अब एक पुतला ही है जिसे मालूम है कि नश्वर होने का सबूत क्या है। वह बनते ही कंकाल और चलते ही ऐसा शव है जो खुद में संबोधित है। बिना किसी पहचान के वह केवल बड़ी पहुंच, प्रतिष्ठित और पहचान वालों का पुतला घोषित हो जाता है। अक्सर घोषणाओं में मशरूफ मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्रियों के पुतले उनकी बराबरी और समकक्ष होने की घोषणा करते हैं। वह एक शक्तिशाली नेता और सत्ता के शिखर पुरुष का पुतला था। वह देश के लिए और बुद्धिजीवी के समर्थन से बना था। बनते ही वह घिनौना, खलनायक और अति दुष्चरित्र के अवतरण में चला गया, इसलिए तोहमतों से बचने के लिए तुरंत जल जाना चाहता था। वह चीख रहा था, 'मुझे जला दो ताकि सनद रहे कि दुष्चरित्र में किसी आला नेता के कारण मेरा जन्म हुआ।' वह सत्ता के शिखर पुरुष के कारण जूते-चप्पलें खा रहा था। जनता उग्र थी, लेकिन पुतला विनम्र था और जलकर मर जाने की भीख मांग रहा था। वह बुद्धिजीवी की ओर हसरत भरी निगाहों से देखकर बोला, 'तुम्हीं जला दो ताकि लोकतंत्र को मालूम हो कि कोई देश को बचाने के लिए पुतला बना।' बुद्धिजीवी पहली बार अपनी हिम्मत व शौर्य से पुतले के शव को जलाने को आतुर था कि कानून-व्यवस्था के पहरेदारों ने उसके हाथों में आए इस अवसर को भी लूट लिया। बुद्धिजीवी से पुतला छीनने की खुशी में सत्ता दल की बैठक हुई जहां फैसला हुआ कि गृह मंत्री के करकमलों से एसपी महोदय को सम्मानित किया जाएगा और आइंदा सारे सार्वजनिक स्थलों पर पुतला रोधक दल तैनात किए जाएं। उदास पुतला सरकार के फैसले से डर गया। -क्रमशः **निर्मल असो**

उत्पादन लगाएगा दाल के दाम पर नियंत्रण, 12.82 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में हो चुकी बुआई

परिवहन विशेष न्यूज

2022-23 के दौरान देश में 15780.56 करोड़ रुपये की दाल का आयात हुआ था जो 2023-24 में दोगुना हो गया। दूसरे देशों से 31 लाख सात हजार करोड़ रुपये की दाल आयात करनी पड़ी। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र राजस्थान उत्तर प्रदेश कर्नाटक आंध्र प्रदेश शीर्ष दाल उत्पादक राज्य हैं। देश में दाल का कुल रकबा लगभग 136 लाख हेक्टेयर है। मानसून रफ्तार में है।

नई दिल्ली। दाल की कीमतें बढ़ने लगीं तो किसानों का रुझान भी दलहन की खेती की ओर होने लगा। रकबे में अप्रत्याशित वृद्धि से दाल की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण लगने की उम्मीद है। ऐसे में वर्ष 2027 तक दाल के मामले में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ने के भी संकेत मिलने लगे हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार दलहन फसलों के रकबे में तेज वृद्धि हो रही है। पिछले खरीफ वर्ष की तुलना में इस वर्ष अबतक 62.32 लाख हेक्टेयर में दाल की बुआई हो चुकी है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि से 12.82 लाख हेक्टेयर अधिक है।

अरहर के रकबे में तीन गुना वृद्धि

अरहर के रकबे में तीन गुना से भी अधिक वृद्धि है। चना, मसूर एवं उड़द का रकबा भी बढ़ा है। केंद्र ने अगले तीन सालों में दाल के मामले में आत्मनिर्भर होने का लक्ष्य तय किया है। मूंग और चना दाल में पहले ही देश आत्मनिर्भर हो चुका है। अन्य दालों का संकट दूर करने का प्रयास है। देश में सबसे ज्यादा अरहर (तुअर) दाल की मांग है। सबसे ज्यादा कमी इसी की है। इसकी कीमतों में पिछले दो वर्ष में ही लगभग दोगुनी वृद्धि हो चुकी है। इतनी तेज वृद्धि किसी अन्य दाल में नहीं देखी गई है। इसका सबसे बड़ा कारण मांग और आपूर्ति में भारी अंतर है। देश में अरहर की उपज वर्तमान में 34 लाख टन है, जबकि खपत 45 लाख टन से ज्यादा। मांग और आपूर्ति में 11 लाख टन का अंतर है।

अरहर की खेती में ये राज्य आगे

इसका असर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। 2022-23 के दौरान देश में 15,780.56 करोड़ रुपये की दाल का आयात हुआ था, जो 2023-24 में दोगुना हो गया। दूसरे देशों से 31 लाख सात हजार करोड़ रुपये की दाल आयात करनी पड़ी। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश शीर्ष दाल उत्पादक राज्य हैं। देश में दाल का कुल रकबा लगभग 136 लाख हेक्टेयर है। मानसून रफ्तार में है। इसलिए उम्मीद भी बढ़ी है। अरहर की खेती में महाराष्ट्र और कर्नाटक आगे हैं, जहां अच्छी बुआई हो रही है।

देश में 15 जुलाई तक अरहर की बुवाई 28.14 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है। यह विगत वर्ष की तुलना में 18.48 लाख हेक्टेयर ज्यादा है। विगत वर्ष इसी अवधि में मात्र 9.66 लाख हेक्टेयर में ही अरहर की बुआई हो पाई थी। बिहार एवं झारखंड में भी पहले अरहर की अच्छी पैदावार होती थी, किंतु हाल के वर्षों में कमी आती गई।

दाम बढ़ने लगे तो रुझान भी बढ़े

अरहर दाल की कीमतों में वृद्धि का सबसे बड़ा कारण है उत्पादन में कमी। किसानों का रुझान अरहर के प्रति इसलिए कम होने लगा कि यह लंबी अवधि की फसल है। लगभग नौ महीने में तैयार होती है। इतने समय में किसान धान और गेहूं की दो फसलें ले चुके होते हैं। अरहर खरीफ फसल है, जो मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर है। मौसम पैटर्न बदल रहा है। कभी बाढ़ तो कभी सूखे के चलते भी किसान अरहर की खेती से दूर होते चले गए, किंतु दाम बढ़ते ही फायदा नजर आने लगा तो रकबे में भी वृद्धि होने लगी।

संपूर्ण खरीदारी की गारंटी

केंद्र ने प्रमुख दालों की संपूर्ण खरीदारी की गारंटी पहले ही दे रखी है। अरहर, उड़द एवं मसूर की उपज का चाहे कितना भी हिस्सा किसान बेच सकते हैं। ऐसे में उम्मीद है कि दाल का रकबा आगे भी बढ़ता रहेगा और पैदावार में भी वृद्धि होगी। दाम पर नियंत्रण के लिए केंद्र ने राज्यों को अरहर और उड़द पर लगी स्टॉक सीमा का सख्ती से पालन एवं निगरानी का भी निर्देश दे रखा है, ताकि जमाखोरी को रोका जा सके।

वित्तीय अनुशासन कायम रखने के लिए मुफ्त की नई योजनाओं से परहेज करेगी सरकार

परिवहन विशेष न्यूज

चालू वित्त वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट में वित्त मंत्री ने राजकोषीय घाटा जीडीपी के 5.1 प्रतिशत रखने का लक्ष्य रखा था लेकिन माना जा रहा है कि अब इस लक्ष्य को कम करके पांच प्रतिशत किया जा सकता है या पांच प्रतिशत के नीचे भी लाया जा सकता है। अगले वित्त वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.5 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य रखा गया है।

नई दिल्ली। चुनावी नतीजों के बाद यूं तो यह अटकलें लगाई जाने लगी है कि सरकार पहले बजट से ही कुछ लोकलुभावन घोषणाएं करें लेकिन अनुशासन को कायम रखना सरकार की पहली प्राथमिकता है और इसीलिए सरकार 23 जुलाई को पेश होने वाले बजट में मुफ्त वाली किसी भी नई योजना से परहेज करेगी। जानकारों का कहना है कि खाद्य, खाद, मनरेगा, उज्ज्वला जैसी विभिन्न योजनाओं की बदौलत सरकार की सब्सिडी पहले ही 3.81 लाख करोड़ तक पहुंच चुकी है।

मुफ्त की किसी नई योजना की शुरुआत करने से सब्सिडी भार और बढ़ेगा और इससे राजकोषीय घाटे में बढ़ोतरी होगी जिससे सरकार की रेटिंग प्रभावित हो सकती है। चालू वित्त वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट में वित्त मंत्री ने राजकोषीय घाटा जीडीपी के 5.1 प्रतिशत रखने का लक्ष्य रखा था, लेकिन माना जा रहा है कि अब इस लक्ष्य को कम करके पांच प्रतिशत किया जा सकता है या पांच प्रतिशत के नीचे भी लाया जा सकता है। अगले वित्त वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.5 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य रखा गया है।

हालांकि फिस्कल रिस्पांस्बिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट (एफआरबीएम) में वर्ष 2018 में हुए संशोधन के मुताबिक राजकोषीय घाटा जीडीपी के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए और कर्ज और जीडीपी का अनुपात 40 प्रतिशत से अधिक नहीं चाहिए। अभी कर्ज का अनुपात भी जीडीपी के 57.2 प्रतिशत है। वित्तीय जानकारों का कहना है कि गत वित्त वर्ष 2023-24 में सरकार के टैक्स राजस्व में बढ़ोतरी हुई है और कर्ज में भी कमी आ रही है, लेकिन मुफ्त की नई योजना लांच करने से राजस्व में बढ़ोतरी का फायदा नहीं मिलेगा।

गत वित्त वर्ष 2023-24 में टैक्स राजस्व में पूर्व के वित्त वर्ष के मुकाबले 13 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी रही और इसका असर यह हुआ कि चालू वित्त वर्ष के अंतरिम बजट में सरकार ने बाजार से 14.1 लाख करोड़ उधार लेने का लक्ष्य रखा जबकि गत वित्त वर्ष में बाजार से सरकार का कर्ज 15.4 लाख करोड़ तक पहुंच गया। वित्तीय जानकारों का कहना है कि आगामी 23 जुलाई को पेश होने वाले पूर्ण बजट में बाजार से ली जाने वाली उधारी के लक्ष्य को कम करके 13.5 लाख करोड़ तक लाया जा सकता है।

बैलेंजिया ने चैन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर किया नए आउटलेट का उद्घाटन

बैलेंजिया ने चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के डोमेस्टिक SHA के टर्मिनल 4 पर अपने नए स्टोर के उद्घाटन की घोषणा की है। इस मौके पर Balenzia की हेड ऑफ स्ट्रेटजी श्रुति गुप्ता ने कहा कि हम एक बार फिर चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर Balenzia की स्टाइल और कम्फर्ट के अनूठे मिश्रण को लाने के लिए उत्साहित हैं। Balenzia मोजे के उद्योग में लगातार सबसे आगे रहा है।

नई दिल्ली। भारत के प्रमुख प्रीमियम सॉक्स ब्रांड Balenzia ने चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के डोमेस्टिक SHA के टर्मिनल 4 पर अपने नए स्टोर के उद्घाटन की घोषणा की है। चेन्नई एयरपोर्ट पहुंचने वाले यात्री अब Balenzia के हाई क्वालिटी, स्टाइलिश और कम्फर्टेबल सॉक्स खरीद सकेंगे।

Balenzia का नया प्रतिष्ठान

एयरपोर्ट के चहल-पहल वाले रिटेल एरिया के सेंटर में स्थित Balenzia के नया स्टोर एक यूनिक शॉपिंग एक्सपीरिएंस प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। क्लासिक और फॉर्मल से लेकर ट्रेंडी और क्विर्की तक, डिजाइन और कलेक्शन की एक विस्तृत सीरीज के साथ, पैसेंजर के लिए कई ऑप्शन उपलब्ध हैं।

कंपनी ने क्या कहा?

इस मौके पर Balenzia की हेड ऑफ स्ट्रेटजी श्रुति गुप्ता ने कहा कि हम एक बार फिर चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर Balenzia की स्टाइल और कम्फर्ट के अनूठे मिश्रण को लाने के लिए उत्साहित हैं। यहां हमारे दूसरे स्टोर का उद्घाटन हमारे ब्रांड की उपस्थिति का विस्तार करने और हमारे प्रीमियम उत्पादों को हमारे मूल्यवान ग्राहकों के लिए आसानी से उपलब्ध कराने के लिए हमारी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

Balenzia को मिलेंगे नए ग्राहक

चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, भारत के सबसे व्यस्त और सबसे गतिशील हवाई अड्डों में से एक होने के नाते, दक्षिण भारत के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है। यह रणनीतिक स्थान हमें विविध और समृद्ध दर्शकों से जुड़ने, हमारे ब्रांड की दृश्यता बढ़ाने और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों यात्रियों के साथ गहरे संबंधों को बढ़ावा देने की अनुमति देता है।

सॉक्स इंडस्ट्री में अव्वल दर्जा

Balenzia मोजे के उद्योग में लगातार सबसे आगे रहा है। कंपनी की ओर से डिजाइन, गुणवत्ता और स्थिरता में नए मानक स्थापितकिए जा रहे हैं। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से गुजरने वाले यात्री अब Balenzia के नवीनतम कलेक्शन को देख सकते हैं और अपनी यात्रा के दौरान मोजे की नई जोड़ी पा सकते हैं। चाहे लंबी दूरी की उड़ान हो, व्यावसायिक यात्रा हो या छुट्टी हो, यात्रियों को आरामदायक और स्टाइलिश रखने के लिए Balenzia के पास परफेक्ट सॉक्स पेयर हैं।

कैश की तुरंत जरूरत शेयर से होगी पूरी! बिना बेचे ही बन जाएगा काम

आप अपने शेयर को बिना बेचे कैश की अर्जेंट जरूरत को पूरा कर सकते हैं। दरअसल शेयर बेचने के बजाय शेयर के बदले लोन लिया जा सकता है। हालांकि इसके लिए सबसे पहले यही समझना जरूरी है कि शेयर के बदले लोन असल में काम कैसे करता है। शेयर के बदले लोन का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह समझ सकते हैं।

नई दिल्ली। कम समय में कैश की अर्जेंट जरूरत है तो आप अपने शेयर के साथ इस जरूरत को पूरा कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि हम शेयर बेचने को लेकर सलाह दे रहे हैं तो ऐसा नहीं है। आप अपने शेयर को बिना बेचे कैश की अर्जेंट जरूरत को पूरा कर सकते हैं। दरअसल, शेयर बेचने के बजाय शेयर के बदले लोन लिया जा सकता है। हालांकि, इसके लिए सबसे पहले यही समझना जरूरी है कि शेयर के बदले लोन असल में काम कैसे करता है।

शेयर के बदले कैसे मिलता है लोन: शेयर के बदले लोन का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह समझ सकते हैं। आपको अपने शेयर बेचने की जरूरत नहीं है इन्हें लोन देने वाले वित्तीय संगठन को जमानत सुरक्षा के तौर पर देना होता है। वित्तीय संगठन लोन की सुरक्षा के बदले ओवरड्राफ्ट सुविधा देते हैं। आप एक सीमा तक पैसों की जरूरत पड़ने पर पैसा का इस्तेमाल कर सकते हैं। सवाल यह आता है कि पैसे पर ब्याज किस तरह तरह लगता है। ब्याज केवल इस्तेमाल की गई राशि और इस्तेमाल किए गए दिनों की संख्या पर ही लगाया जाता है।

कैसे चुका सकते हैं लोन राशि: अब बात करें लोन की राशि चुकाने की तो इस राशि को बिना किसी पेनल्टी के चुकाया जा सकता है। अमूमन लोन की इस राशि को चुकाने के लिए एक वर्ष की समयावधि दी जाती है। हालांकि, इस लोन को रिन्यू करवाने की सुविधा भी मौजूद रहती है।

इनकम टैक्स सरकार के लिए सबसे बड़ा कमाई का जरिया, राजस्व में कॉरपोरेट टैक्स और जीएसटी पीछे छूटा

परिवहन विशेष न्यूज

प्रमुख कर श्रेणियों में सबसे तेज वृद्धि व्यक्तिगत आयकर में दर्ज की गई है। कम निजी खपत वृद्धि और गिरती मुद्रास्फीति के बावजूद वित्त वर्ष 2023-24 में आयकर और जीएसटी संग्रह दोनों ने प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की। रिपोर्ट में भारत के समग्र सकल कर संग्रह में 13-15 प्रतिशत चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) का अनुमान लगाया है जिसमें वित्त वर्ष 2024-25 में 11 प्रतिशत वृद्धि की उम्मीद है।

नई दिल्ली। वित्तीय सेवाएं प्रदान करने वाली आनंद राठी कंपनी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, व्यक्तिगत आयकर सरकार के लिए सबसे बड़ा राजस्व का माध्यम बनकर उभरा है और इसने कॉरपोरेट टैक्स और जीएसटी दोनों को पीछे छोड़ दिया है। सकल कर संग्रह में जीएसटी, कॉरपोरेट टैक्स और व्यक्तिगत आयकर की हिस्सेदारी 30-30 प्रतिशत के आसपास है और वित्त वर्ष 2018-19 से इनके संग्रह में काफी भिन्नता देखने को मिली है। कॉरपोरेट टैक्स की वृद्धि दर सबसे धीमी और सबसे अस्थिर रही है और इसका मुख्य कारण दरों में कटौती किया जाना है।

इसके विपरीत, व्यक्तिगत आयकर में सबसे तेजी से वृद्धि हुई है और इसने सरकार के लिए सबसे बड़ा राजस्व जुटाने वाले कारपोरेट टैक्स की जगह ले ली है। जीएसटी ने वित्त वर्ष 2022-23 में कॉरपोरेट कर संग्रह को पीछे छोड़ दिया था। प्रमुख करों में सीमा शुल्क सबसे कम राजस्व अर्जित करने वाला टैक्स है। खास बात यह है कि वित्त वर्ष 2023-24 में कॉरपोरेट आय में उल्लेखनीय उछाल के बावजूद कॉरपोरेट टैक्स की वृद्धि मामूली रही और यह आयकर और जीएसटी संग्रह में दिखने वाले रुझानों के विपरीत है।

प्रमुख कर श्रेणियों में सबसे तेज वृद्धि व्यक्तिगत आयकर में दर्ज की गई है। कम निजी खपत वृद्धि और गिरती मुद्रास्फीति के बावजूद, वित्त वर्ष 2023-24 में आयकर और जीएसटी संग्रह दोनों ने प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की। रिपोर्ट में भारत के समग्र सकल कर संग्रह में 13-15 प्रतिशत चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) का अनुमान लगाया है, जिसमें वित्त वर्ष 2024-25 में 11 प्रतिशत वृद्धि की उम्मीद है।

पहली तिमाही में वस्तु निर्यात में 5.84 प्रतिशत की बढ़ोतरी, जून में 2.55 प्रतिशत हुआ इजाफा

वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने बताया कि निर्यात में आगे भी बढ़ोतरी जारी रहने की उम्मीद है क्योंकि वैश्विक स्तर पर महंगाई में कमी आ रही है और विकास भी हो रहा है। इससे निश्चित रूप से भारतीय निर्यात को समर्थन मिलेगा। उन्होंने कहा कि वस्तु व सेवा मिलाकर इस साल अप्रैल-जून में 200 अरब डॉलर का निर्यात हो चुका है।

नई दिल्ली। पिछले वित्त वर्ष 2023-24 के विपरीत चालू वित्त वर्ष 2024-25 में वस्तु निर्यात में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। गत जून में वस्तुओं के निर्यात में पिछले साल जून के मुकाबले 2.55 प्रतिशत की तो वस्तुओं के आयात में 4.98 प्रतिशत की बढ़ोतरी रही। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में वस्तु निर्यात में 5.44 प्रतिशत का इजाफा रहा। जून में सेवा निर्यात में पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी रही। वस्तुओं के निर्यात में बढ़ोतरी से मैन्यूफैक्चरिंग में तेजी आएगी जिससे नए रोजगार के सृजन में मदद मिलेगी।

वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने बताया कि निर्यात में आगे भी बढ़ोतरी जारी रहने की उम्मीद है क्योंकि वैश्विक स्तर पर महंगाई में कमी आ रही है और विकास भी हो रहा है। इससे निश्चित रूप से भारतीय निर्यात को समर्थन मिलेगा। उन्होंने कहा कि वस्तु व सेवा मिलाकर इस साल अप्रैल-जून में 200 अरब डॉलर का निर्यात हो चुका है और बढ़ोतरी की यही रफ्तार रही तो चालू वित्त वर्ष में कुल निर्यात 800 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है।

बर्थवाल ने बताया कि निर्यात में तेजी के लिए मंत्रालय छह सेक्टर और 20 देशों पर मुख्य रूप से फोकस कर रहा है क्योंकि इन सेक्टर में निर्यात बढ़ाने की काफी गुंजाइश है। इन छह सेक्टर में इंजीनियरिंग गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल व अपैरल, फार्मा, केमिकल्स व कृषि संबंधी शामिल हैं। वाणिज्य विभाग के मुताबिक जून में 35.1 अरब डॉलर का निर्यात तो 56.1 अरब डॉलर का आयात किया गया।

जून में इंजीनियरिंग गुड्स के निर्यात में 10.27 प्रतिशत, इलेक्ट्रॉनिक्स में 16.91 प्रतिशत, रेडीमेड गारमेंट्स में 3.68 प्रतिशत, ड्रग्स व फार्मा में 9.99 प्रतिशत तो काफी के निर्यात में 70 प्रतिशत की बढ़ोतरी रही, लेकिन लेदर व लेदर उत्पाद के निर्यात में 2.17 प्रतिशत, हैंडीक्राफ्ट्स में 16.56 प्रतिशत तो जेम्स व ज्वैलरी में 1.42 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। जून में सोने के आयात में पिछले साल जून की तुलना नें 38 प्रतिशत की गिरावट रही, लेकिन चांदी के आयात में 377 प्रतिशत का इजाफा रहा।

परीक्षा में सुरक्षा की कमजोर कड़ियां

विजय गर्ग

सर्वोच्च न्यायालय अब चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आयोजित की गई पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट-यूजी 2024 से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई अगले हफ्ते करेगा। पिछले महीने नतीजे घोषित होने के बाद से ही राष्ट्रीय परीक्षा एजंसी यानी एनटीए की साख पर देशभर में सवाल उठ रहे हैं। पटना पुलिस ने अदालत में दावा किया था कि नीट-यूजी का पर्चाफोड़ हुआ है। इस साल नीट-यूजी के लिए तेईस लाख से अधिक उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था।

पर्चाफोड़ की इस घटना ने सरकार के सामने संकट खड़ा कर दिया है। यूजीसी नेट परीक्षा भी आयोजित होने के एक दिन बाद रद्द कर दी गई थी। हाल ही में लगातार चार परीक्षाओं- नीट-यूजी, यूजीसी नेट, सीएसआईआर-नेट और अब नीट पीजी प्रवेश परीक्षाएं या तो रद्द या स्थगित कर दी गईं, जिससे करीब सैंतीस लाख अभ्यर्थी और उनके अभिभावक सीधे प्रभावित हुए हैं। इन पर्चाफोड़ से न न सिर्फ लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर है, बल्कि एनटीए की विश्वसनीयता भी सवालों के घेरे है। पूरी जांच के बाद ही परतें खुलेंगी, पर र एनटीए पर उठ रहे सवालों के पीछे सबसे बड़ी वजह है निजी एजेंसियों को दिया जाने वाला ठेका। भारत में अक्सर पर्चाफोड़ की खबरें आती रहती हैं। यह बीमारी कोई नई नहीं है , इसके चलते पहले भी कई परीक्षाओं को रद्द करना पड़ा है 1997 में आइआइटी जेईई और 2011 में आल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं पर्चे भी बाहर आ चुके । यह एक ऐसा नासूर है जो समय के साथ और ज्यादा गहरा होता गया है। मीडिया रपटों के मुताबिक पिछले सात वर्षों में देश के अलग-अलग राज्यों में सत्तर से अधिक परीक्षाओं के पर्चाफोड़ हुए हैं, जिससे करीब दो करोड़ युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है। पर्चाफोड़ और परीक्षा रद्द होने की खबरों के साथ युवाओं के सपने चकनाचूर हो जाते हैं। साथ ही, मां-बाप द्वारा पेट काट कर भेजा गया पैसा भी व्यर्थ चला जाता है। सरकारें इसे लेकर गंभीर रहीं हैं, जिसका जवाब ये युवा उम्मीदवार कई सालों से तलाश रहे हैं। हर बार जब तक जांच होती है, तब तक दूसरा पर्चाफोड़ हो जाता है।

राज्यों में भले सरकारें अलग-अलग पार्टियों की हैं, मगर पर्चाफोड़ का तरीका सब जगह एक जैसा है। अव्वल तो परीक्षाएं नियमित अंतराल पर होती नहीं, पद सालों-साल खाली पड़े रहते हैं, लेकिन भर्ती नहीं होती और जो होती भी है, वह पर्चाफोड़ की भेंट चढ़ जाती है। पचफोड़ की अलग-अलग विधि होती है, जैसे असम में परीक्षा शुरू होने के के कुछ सेकंड में पूरा पर्चा वाटूर वाट्सएप पर पर प्रसारित कर दिया गया। मध्यप्रदेश पर्चाफोड़ के आरोपियों ने मुंबई की उस कपंनी के सर्वर में सेंधमारी की थी, जिसे परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी दी गई थी। वहीं, यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में परिवहन निगम की जिस कंपनी को पर्चे छापने के बाद गोदामों में रखने की जिम्मेदारी दी गई, उसकी मिलीभगत से पर्चाफोड़ किया गया था। कई बार परीक्षा केंद्रों से भी पर्चाफोड़ किया जा चुका है।

पर्चाफोड़ न रोक पाना एक अक्षम्य अपराध है। यह केवल परीक्षा व्यवस्था खामी नहीं, बल्कि लाखों युवाओं के सपनों को चकनाचूर करने का अपराध है। भारत की लगभग 65 फीसद आबादी युवा है। उनके सपने बड़े हैं। वे परिश्रमी और प्रतिभाशाली हैं, तमाम कठिनाइयों एवं अभावों से लड़ते जूझते कई-कई वर्षों तक इन प्रतियोगी परीक्षाओं की जी-तोड़ तैयारी करते हैं। हालांकि पर्चाफोड़ और नकल कराने वालों के खिलाफ राज्य सरकारों ने सख्त कानून बनाए हैं, लेकिन इन सबके बावजूद इस प्रवृत्ति पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। सवाल है कि आरोपियों के पकड़े जाने के बाद भी वे आसानी से कैसे छूट जाते हैं, जबकि कानून में तो सजा का कड़ा प्रावधान है। कड़ी सजा के प्रावधान भर से इस समस्या का कोई असरदार हल नहीं निकलने वाला है। हर साल सिविल सेवा परीक्षा में दस लाख से अधिक अभ्यर्थी होते हैं, फिर भी यूपीएससी सुरक्षित परीक्षा आयोजित करता है। जहां तक आनलाइन पर्चे की बात है, प्रौद्योगिकी आधारित परीक्षा / आनलाइन परीक्षाओं के निरंतर उपयोग से इसमें रिसाव का खतरा रहेगा खतरा बढ़ना तय है, अब एआइ का समय है, ऐसे में यह भविष्य में बड़ा खतरा होगा। अगर गृह मंत्रालय की वेबसाइट में सेंधमारी हो सकती है, तो ये परीक्षाएं कैसे सुरक्षित मानी जा सकती हैं ?₹

अब अकेली, व्यक्तिगत या छोटे समूह स्तर के घोटाले नहीं रह रह गए हैं। जैसे-जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं का दौर तेजी से बढ़ा

है, अनियमितता की प्रकृति भी भी बहुत बड़ी हो गई पर पूरी राजनीतिक संपर्क वाली नियुक्तियों पर है। भर्ती आयोग तरह रोक लगाई जाए। कई केंद्राध्यक्ष सहित सभी के लिए मोबाइल फोन प्रतिबंधित होने चाहिए। पर्चा तैयार करने से लेकर परीक्षा केंद्र पर वितरण तक सैकड़ों लोग शामिल होते हैं, इसलिए ऊपर से नीचे तक सभी की जिम्मेदारी तय हो। अधिकतर परीक्षा केंद्र निजी संस्थानों में होते हैं, उनमें मानक के अनुरूप नहीं हैं। सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 में भी कई खामियां हैं, जिसमें तत्काल की आवश्यकता है। सार्वजनिक परीक्षा के पर्चाफोड़ का अपराध बड़े पैमाने पर जनता को प्रभावित करता है, इससे राज्य के खजाने पर भी भारी वित्तीय बोझ है। पड़ता सुधार अधिनियम में कारावास की न्यूनतम अवधि तीन साल है, जिसे दस साल करना चाहिए। वहीं, निर्धारित सजा की राशि अपराध की गंभीरता के अनुरूप नहीं है। इसमें समयबद्ध जांच का कोई प्रावधान नहीं है। अधिनियम के तहत किसी अपराध के लिए जुर्माना अदा न करने की स्थिति में कारावास की अतिरिक्त सजा के साथ-साथ अपराधी की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान भी शामिल किया जाना चाहिए। इसके अलावा, अनुचित साधनों का लाभ उठाने में शामिल उम्मीदवार को भविष्य की किसी भी परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए।

सरकारी विभागों में नौकरी पाने के लिए छात्र कमरतोड़ मेहनत करते हैं। मगर ईमानदारी से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों का हौसला अब हार रहा है। आज उनके अंदर निराशा है और इससे उनके परिवार का मनोबल भी टूट रहा है। परीक्षा एजेंसी का अपना प्रिंटिंग प्रेस हो हो या एक घंटे पहले साफ्ट कापी को 'कोड लाक' के माध्यम से सीधे भेजा जाए और परीक्षा केंद्र में मौजूद अभ्यर्थियों को वहीं प्रिंट करके वितरित किया जाए। इस विधि से प्रश्नपत्र प्रेस छपाई से थोड़े महंगे जरूर होंगे, पर सुरक्षित होंगे। पूरी प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए पर्चा बनाने से लेकर परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए। किसी कोचिंग संस्थान की संलिप्तता मिलने पर उसको भी बंद किया जाए। पर्चा तैयार होने से लेकर उन्हें परीक्षा केंद्रों पर पहुंचाने में शामिल सभी लोगों की जिम्मेदारी तय हो।

संगम विश्वविद्यालय के छात्र स्वर्णिम माहेश्वरी ने की एनपीटीईएल परीक्षा में उल्लेखनीय सफलता हासिल

परिवहन विशेष अनूप कुमार शर्मा

भीलवाड़ा। स्थानीय संगम विश्वविद्यालय में बी.टेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के छात्र स्वर्णिम माहेश्वरी ने एनपीटीईएल परीक्षाओं में एक चमकते सितारे के रूप में उभरे हैं। स्वर्णिम की प्रभावशाली उपलब्धियों ने उन्हें एनपीटीईएल सुपरस्टार का प्रतिष्ठित खिताब दिलाया है। उन्होंने तीन चुनौतीपूर्ण पाठ्यक्रमों में शीर्ष स्थान हासिल करके अपनी शैक्षणिक क्षमता का प्रदर्शन किया है जिनमे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का परिचय, (आईआईटी दिल्ली द्वारा संचालित), मशीन लर्निंग का परिचय- आईआईटी खड़गपुर द्वारा, डेटा साइंस के लिए पायथन, (आईआईटी मद्रास द्वारा) पाठ्यक्रमों में स्वर्णिम का शानदार प्रदर्शन अकादमिक उत्कृष्टता के प्रति उनके समर्पण और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियाँ अन्य छात्रों और शिक्षकों के लिए समान रूप से प्रेरणा का काम करती हैं, जिससे शीर्ष स्तरीय प्रतिभाओं के पोषण के लिए संगम विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा मजबूत होती है। स्वर्णिम महेश्वरी को इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए कुलपति प्रो करुणेश सक्सेना, प्रो वीसी प्रो मानस रंजन पाणिग्रही, रजिस्ट्रार प्रो राजीव मेहता, डीन स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग प्रो आरके सोमानी, डेप्युटी डीन डा विकास सोमानी आदि ने बधाई दी और उनकी शैक्षणिक यात्रा में निरंतर सफलता की कामना करी। एनपीटीइएल की सफलता को देखते हुए स्वर्णिम को आईआईटी मद्रास से इंटर्नशिप एवं एमटेक का ऑफर आया है जिसको स्वर्णिम ने स्वीकार किया है

अंतरराष्ट्रीय माहेश्वरी कपल क्लब की भीलवाड़ा शाखा द्वारा''चर्चा चाय पर'' का आयोजन

भीलवाड़ा। अंतरराष्ट्रीय माहेश्वरी कपल क्लब की भीलवाड़ा शाखा के संगठन सचिव मधुसूदन राठी व लीला राठी द्वारा आज के भाग-दौड़ भरे जीवन में योग द्वारा स्वस्थ कैसे रहा जा सकता है, इस विषय पर चर्चा चाय पर का आयोजन किया गया। अहमदाबाद से पधारे योगाचार्य व क्लब के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष मुकेश कोठारी ने योग व प्राणायाम के महत्व व इनके अभ्यास से किस बीमारी का किस योग व प्राणायाम से उपचार किया जा सकता है, इस बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। मुख्य अतिथि के रूप में क्लब के राष्ट्रीय महासचिव डॉ अशोक सोडानी व अनिता सोडाणी, राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष सुरेश सोनी व डॉ सुमन सोनी व विशिष्ट अतिथि के रूप में जिलाध्यक्ष सुनिल जागेटिया, डॉ चेतना जागेटिया, नीलम दरगड़, बी एल, कांता मेलाना, रामचंद्र जी मूंदड़ा, सुमन बाहेती उपस्थित थे। इस अवसर पर कार्यक्रम संयोजक द्वारा मुकेश व रीतु कोठारी एवं सुमन व मुकेश तोषनीवाल का स्वागत-अभिनंदन किया गया।

त्रिशा अस्पताल आग ,बच्चे के पिता विजय बेहरा ने शिशुभवन अस्पताल को जिम्मेदार ठहराया

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड उडीशा

भुबनेस्वर् :कटक पुरीघाट त्रिशा अस्पताल में आग लगने की घटना। 17 बच्चों में से एक की रविवार को शिशुभवन मे मौत हो गई । हालांकि, बच्चे के पिता विजय बेहरा ने शिशुभवन अस्पताल को जिम्मेदार ठहराया है । हालांकि वह इलाज के लिए सबसे पहले शिशुभवन हॉस्पिटल आए थे, लेकिन वहां आईसीयू नहीं होने की बात कहकर उन्हें लौटा दिया गया।उन्होंने सवाल किया कि जब आईसीयू में कोई बेड नहीं था तो अनाथालय में इतने सारे बेड कैसे उपलब्ध हो गए। बच्ची की तबीयत खराब होने पर विजय उसे पहले भद्रक अस्पताल ले गया। वहां से 7 तारीख को बच्चे को शिशुभवन लाया गया । एक सुरक्षा गार्ड ने उसे एक निजी अस्पताल में ले जाने के लिए कहा और उसे उक्त अस्पताल का फोन नंबर दिया।

बाद में, विजय ने बच्चे को ले लिया और उसे त्रिशा में डाल दिया। शनिवार को त्रिशा में आग लगने के बाद बच्ची का इलाज ठीक से नहीं हो सका । उनकी तबीयत और भी खराब हो गई । गंभीर हालत में उसे शिशुभवन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। 13 तारीख की देर रात जब बच्चे की मौत हो गई । मृत बच्चे की स्वास्थ्य समस्याएं जटिल थीं । नर्सरी के अधीक्षक ने बताया कि उसकी मौत बीमारी से हुई है । इसी तरह एससीबी में भर्ती 18 लोगों में से 4 लोगों को छुट्टी दे दी गई है । अस्पताल सूत्रों के अनुसार एसएनसीयू में 3, आईसीयू में 4 और जनरल वार्ड में 7 लोगों का इलाज चल रहा है ।

हजरत इमाम हुसैन साहब की शहादत की याद में मनाया जाता हैं पवित्र मोहर्रम का पर्व : वरिष्ठ समाजसेवी मुशरफ खान

अपील - पवित्र मोहर्रम का पर्व गम का प्रतीक हैं इसे आपसी प्रेम, सौहार्द व शांतिपूर्ण माहौल में सादगी एव अकीदत के साथ मनाएं : वरिष्ठ समाजसेवी मुशरफ खान

आगरा। पवित्र मोहर्रम का पर्व गम का प्रतीक हैं। इस्लाम धर्म के मानने वाले अनुयायियों के लिए मोहर्रम एक पवित्र पर्व है। जिसे मुस्लिम भाइयों द्वारा प्रतिवर्ष इसे सादगी एव अकीदत के साथ शौहार्द भरे वातावरण में अमन-चैन, शांति, प्रेम एवं आपसी भाईचारे के साथ हजरत इमाम हुसैन साहब की सहादत की याद में मिलजुल कर मनाया जाता है। वही, इस अवसर पर ताजिया का जुलूस निकालकर विभिन्न जगहों पर मेला का भी आयोजन किया जाता है।

आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत विभिन्न संप्रदाय के सभी धर्मगुरुओं, सम्भ्रान्त व्यक्तियों एवं भारत के प्रतिष्ठित नागरिकों एवं समाज के लोगों से अपील करते हुए वरिष्ठ समाजसेवी मुशरफ खान ने कहा आगामी त्यौहारों नाग पंचमी, मुहर्रम, रक्षाबंधन एवं श्रावण मास, कांवड़ यात्रा, को स्वच्छ वातावरण एवं शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए विभिन्न संप्रदाय के धर्मगुरुओं, एवं जनपद के प्रतिष्ठित नागरिकों से हमारी अपील हैं कि पवित्र मोहर्रम का पर्व गम का प्रतीक हैं। हजरत इमाम हुसैन साहब की सहादत की याद में इसे सादगी एव अकीदत के साथ शौहार्द भरे वातावरण में भाईचारे से मिलजुल कर मनाया जाता हैं। सभी त्यौहार शौहार्द भरे वातावरण में अमन-चैन, शांति, प्रेम एवं भाईचारे के साथ मिलजुल कर मनाएं क्योकि हमारे जनपद में भाईचारे एवं गंगा जमुनी तहजीब का गौरवशाली इतिहास रहा है, हमारे आगरा में हर पर्व त्यौहार मिलजुल कर सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाए जाने की परंपरा रही है। सभी लोग उसी परंपरा को कायम रखें। उन्होंने शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में पर्व मनाए जाने को लेकर अपील करते हुए कहा कि जिले का इतिहास शांति सौहार्दपूर्ण भाईचारे का रहा है। अब तक सभी समुदाय के लोग सभी पर्वों को शांतिपूर्वक मनाने में अपना योगदान देते रहे हैं। ऐसे में आगामी मोहर्रम पर्व भी शांतिपूर्ण संपन्न हों। इसके लिए सभी लोग एकजुट होकर प्रयास करें। साथ ही बिना लाईसेंस के मेला का आयोजन, डीजे, पटाखा एवं हथियार प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंधित रखा गया है। ताजिया जुलुस के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है। बिना लाइसेंस के ताजिया जुलुस नहीं निकाली जाय। जुलुस के लिए जारी किये गये लाइसेंस में जुलुस का मार्ग, समयावधि निर्धारित रहेगा, जिसका अनुपालन करना होगा। जुलुस में आग्नेयशास्त्र का प्रदर्शन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इसके साथ ही डीजे प्रतिबंधित है, केवल लाउडस्पीकर की अनुमति रहेगी, लेकिन इसके लिए अनुमण्डल पदाधिकारी की अनुमति जरूरी होगी। जुलुस का विडियोग्राफी करानी होगी।

श्री खान ने आगामी पवित्र मुहर्रम त्योहार के मद्देनजर लोगों को जागरुक करते हुए आगे कहा कि बीते दिनों हुई हाथरस की ह्रदयविदारक घटना के मद्देनजर साबधानी के दृष्टिगत आगामी त्यौहारों को लेकर शासन - प्रशासन और पुलिस अलर्ट मोड पर रहे और ताजिया रखने और निकालने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। हातात-ए-पेशे नजर पर्व को मानने को लेकर जो सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी हुई है, उसकी हमें पालन करने की कोशिश करनी होगी, जिससे मौजूदा जिला प्रशासन और किसी अन्य समुदाय के लोगों को ठेस पहुंचने और दिक्कतों का सामना न करना पड़े। ऐसे में हमें मिलजुल कर अमन शांति से बिना किसी जोर जबरदस्ती के साथ अपने त्योहार को मनाने की जरूरत है। क्योकि जिस बाग का माली ना हो यह बाग, बाग नहीं रहता, ऐसे में हम अपने युवा पौड़ी नौजवान वर्ग के युवाओं को मौजूदा हालात के मद्देनजर समझाकर, जागरुक करते हुए त्योहार मनाने के लिए सवक देने की सख्त जरूरत है। इसलिए आगामी सभी त्योहारों पर कोई भी नई परंपरा त्यौहार में ना डाली जाए और जिन रूटों से पूर्व में कांवड़ यात्रा व ताजिया निकलती रही है, उन रूटों से ही कावड़ यात्रा व ताजिया निकाले अनावश्यक रूप से कोई नई परंपरा ना डालें। ताजियेदार किसी भी नई परंपरा का प्रयोग न करके शांतिपूर्ण ढंग के ताजिया का जुलूस निकलने वाले परम्परागत रास्तो से अलम व ताजिये के जुलुस निकाले, कोई नई परम्परा न डाले, जिससे व्यवधान पैदा हो। सभी ताजिया की ऊंचाई 08 से 10 फिट यानी पहले के ही बराबर रखे तथा कोई फेरबदल न करे और पूर्व से निर्धारित मार्गो से ही जुलुस निकाले तथा कोई नयी परम्परा न डाले जिससे माहौल में खलल पड़े। उन्होंने ने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि आप सभी लोग जोश में होश न खोये एव बुजुर्गों की सलाह पर ही त्यौहार को मनाये। अलम एव ताजियों का जुलूस निध्र्गारित मार्गो से ही निकाले तथा सकारात्मक सोच के साथ ही पर्व को मनाये तथा स्वयं अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करे क्योंकि अमन चेन बनाये रखने में आप सभी लोगो की बड़ी भूमिका होती है। सभी लोग पुलिस का सहयोग करे। पुलिस आप लोगो के सहयोग के लिए हर समय मौजूद हैं। उन्होंने लोगो को सचेत करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर कोई भी भड़काऊ पोस्ट ना डालें, यदि किसी ने महौल को खराब करने की कोशिश की तो उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी। बिना कोई नई परम्परा डाले हुये पूर्व की भांति त्यौहार मनाऐं और पुलिस एवं प्रशासन का पूर्ण सहयोग करें। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखी जा रही हैं। यदि किसी प्रकार अफवाह या भ्रान्ति फैलाई जाती है तो तत्काल कार्यवाही होंगी। इसलिए किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। शासन की गाइडलाइंस का पालन करें। बारह फिट से अधिक ताजिये नहीं होने चाहिए। मोहर्रम के दौरान सामाजिक तत्वों पर पुलिस प्रशासन की कड़ी नजर रहेगी। कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे किसी दूसरे की भावना को ठेस पहुंचे। पुलिस की नजर सोशल मीडिया पर विशेष तौर पर रहेगी तथा सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आगामी पर्व के अवसर पर सुरक्षा की दृष्टिकोण से पुख्ता व्यवस्था रहेगी। सभी चिन्हित एवं संवेदनशील स्थानों, चौक चौराहों पर दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति रहेगी। सोशल मीडिया पर नजर रखी जायेगी। इसके लिए साईबर सेल एक्टीव रहेगा। उपद्रवी एवं असमाजिक तत्त्वों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई तय मानी जाय। अफवाह फैलाने वाले भी नहीं बचेंगे। उन्होने कहा कि सामप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले कंन्टेंट को फॉरवर्ड करने से बचा जाय। निर्धारित रूट से ही जुलुस की अनुमति रहेगी। किसी भी परिस्थिति में रूट चेंज नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ड्रोन के द्वारा विडियाग्राफी करायी जाएगी एवं उचें भवनों पर नजर रखी जाएगी। नशा एवं मादक पदार्थों का सेवन कर जुलुस में चलने वालों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसलिए हमारा सभी से पुनः विनम्र निवेदन हैं कि सभी त्यौहार शौहार्द भरे वातावरण में अमन-चैन, शांति, प्रेम एवं भाईचारे के साथ मिलजुल कर मनाएं।

अंक ज्योतिष का रहस्य: जानिए अपने जीवन का उद्देश्य : प्रांशु विरमानी

न्यूमेरोलॉजी में किए गए अपने सफर के बाद मुझे सबसे ज्यादा एक सवाल बहुत प्रेरित करता था: ₹मैं यहां क्यों हूँ ?₹ मुझे अपनी जीवन रेखा संख्या को समझना था और यह जानना था कि यह मेरे भूमिका और पूरे जीवन के उद्देश्य को क्या प्रकट करता है। इस सवाल के उत्तर के लिए, मैंने न्यूमेरोलॉजी, न्यूमेरो-वास्तु, वास्तु, एस्ट्रो-वास्तु, और फेंगशुई में गहराई तक खोज की। बहुत से लोग भी अपनी जीवन रेखा और उद्देश्य के बारे में स्पष्टता की तलाश में हो सकते हैं। न्यूमेरोलॉजी इन सवालों में गहराई तक जानकारी प्रदान कर सकती है, जो आपको अधिक समझ और आत्मविश्वास के साथ जीवन को संभालने में मदद करती है।

न्यूमेरोलॉजी क्या है ?: न्यूमेरोलॉजी संख्याओं का अध्ययन है और उनके जीवन पर पर्यावरणीय प्रभाव को दर्शाता है। प्रत्येक संख्या की एक अद्वितीय ध्वनि होती है जो आपके व्यक्तित्व, सामर्थ्य, चुनौतियों और आपके जीवन के उद्देश्य के बारे में बताता है। अपनी जन्म तिथि और नाम का विश्लेषण करके, हम छिपे सत्यों को उजागर कर सकते हैं और आपके भविष्य के लिए मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। जीवन रेखा संख्या क्या है ? न्यूमेरोलॉजी में, आपकी जीवन रेखा संख्या आपकी जीवन की प्रयोजन और उन मूल गुणों का शक्तिशाली संकेत है जो आपकी यात्रा को परिभाषित करते हैं। अपनी जीवन रेखा संख्या को समझकर, आप अपनी शक्तियों, चुनौतियों और उस विशेष उद्देश्य को समझ सकते हैं जिसके लिए आप यहां पर हैं।अब आइए जानें कि हर जीवन रेखा संख्या का मतलब क्या है, अपनी अपनी संख्या कैसे गणना करें और यह क्या प्रकट करती है आपकी यात्रा के बारे में।

अपनी जीवन रेखा संख्या और उनके मतलब संख्या 1: नेता उद्देश्य: आप यहां नेतृत्व करने और प्रेरित करने के लिए हैं। अपनी व्यक्तित्वता को गले लगाएं और अपनी प्रयासों में नेतृत्व करें। आपमें उस स्थिरता और साहस की शक्ति है जिससे जीवन के विभिन्न पहलुओं में नई पथों को प्रारंभ करने और नवाचार करने की क्षमता होती है। आपकी यात्रा दूसरों के लिए एक मिसाल स्थापित करने के बारे में है, जिसमें साहस, दृढ़ता, और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक दृष्टिकोण है। संख्या 2: कूटनीतिज्ञ उद्देश्य: शांति और संतुलन बनाने के लिए आप हैं। आपकी सहानुभूति दिव्यता का उपयोग करें ताकि अपने आसपास में समर्थन को बढ़ावा दे सकें। आपका काम है लोगों के बीच सेतुबंध बनाना, संघर्षों को मध्यस्थता करना, और एकता और सहयोग का एक भावनात्मक माहौल लाना। संबंधों को न्योता देकर और विभिन्न परिप्रेक्ष्यों को समझकर, आप एक समरस दुनिया को संवालने में मदद कर सकते हैं। संख्या 3: संवादक उद्देश्य: आप यहां अभिव्यक्ति और प्रेरणा के लिए हैं। अपनी रचनात्मकता और उत्साह को दुनिया के साथ साझा करें। आपका पथ अपनी अभिव्यक्ति की प्रतिभा का उपयोग करके खुशी और उत्कृष्टता लाने, दूसरों को उत्तेजित करने और विचारों को प्रभावी ढंग से संवाद करने के बारे में है। कला, शब्दों, या अन्य अभिव्यक्ति के माध्यम से, आप अपने आसपास के लोगों पर एक दीर्घकालिक प्रभाव डाल सकते हैं, जो उन्हें प्रेरित और सकारात्मकता के रास्ते पर ले जाता है। संख्या 4: निर्माता उद्देश्य: स्थिरता आपका कुंजी है। जीवन के सभी क्षेत्रों में मजबूत नींव बनाने पर ध्यान केंद्रित करें। आपकी भूमिका है व्यवस्था और संरचना बनाने की, सुनिश्चित करने की कि आपको छू गया हर चीज संगठित और विश्वसनीय है। एक मजबूत आधार स्थापित करके, आप दूसरों को समृद्धि और स्थायित्व में बढ़ावा देते हैं, जो दीर्घकालिक सफलता और सुरक्षा में योगदान करता है। संख्या 5: साहसी उद्देश्य: नई चीजों को स्वीकार करें और स्वतंत्रता का मूल्य दें। विविधता की तलाश में हो और एकरूपता से बचें। आपकी यात्रा अज्ञात का अन्वेषण करने, जोखिम उठाने, और जीवन को उसकी पूर्णता में अनुभव करने के बारे में है। परिवर्तन और अनुकूलन को अपनाकर, आप दूसरों को उनकी सीमाओं से मुक्त होने और जीवन की विशाल संभावनाओं की खोज करने के लिए प्रेरित करते हैं। संख्या 6: पोषणकर्ता उद्देश्य: दूसरों को पोषण और समर्थन दें। आपके चारों ओर स्नेह और स्थिरता प्रदान करें। आपका कार्य है एक दयालु और समर्थनशील माहौल बनाना, जहां लोग महसूस करते हैं कि वे मूल्यवान और प्यारे हैं।

दया और सहानुभूति के कार्यों के माध्यम से, आप दूसरों को खिलाने में मदद करते हैं, जो सभी के भले के लिए समृद्धि बढ़ाता है और समूहवाद को बढ़ाता है। संख्या 7: खोजी/ अन्वेषक उद्देश्य: आप गहरे ज्ञान और समझ की खोज करते हैं। जीवन के रहस्यों में डूबें और अपनी दृष्टिकोण साझा करें। आपकी यात्रा में सत्य, ज्ञान, और आध्यात्मिक उद्घाटन के लिए एक खोज होती है। अस्तित्व के गहरे पहलुओं को अन्वेषण करके, आप दूसरों को गहरी अंतर्दृष्टि और मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं, जिससे उन्हें अपने आत्मिक सफर को संचालित करने में मदद मिलती है। संख्या 8: प्रभावक उद्देश्य: समृद्धि और प्रभाव प्राप्त करें। सामग्री और आध्यात्मिक पुर्षार्थों को संतुलित करें। आपका कार्य है अपनी शक्ति और प्रभाव का उपयोग करना ताकि दुनिया में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सके। सामूहिक सफलता और न्यायमूलक जनसंख्या के साथ संधि बनाकर, आप दूसरों को एक योग्य और समृद्ध समाज की ओर नेतृत्व कर सकते हैं, जिससे बड़े पैमाने पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाला जा सकता है। संख्या 9: संत उद्देश्य: अपने ज्ञान और दया के साथ दुनिया को ठीक करें। एक मार्गदर्शक और चिकित्सक के रूप में अपनी भूमिका को स्वीकार करें। आपकी यात्रा में दया, दान करने की और समझ का भूमिका है, जिससे आप मानवता की सेवा कर सकते हैं और भेदभाव, चारित्र, और समझ के माध्यम से एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। न्यूमेरोलॉजी रीडिंग क्यों लेनी चाहिए ? अपनी असली स्वभाव, क्षमताओं, और अपने जीवन में कार्य का पता लगाएं। अपनी ताकतों और सुधार के क्षेत्रों में अंतर्दृष्टि प्राप्त करें। अपने जीवन का मिशन स्पष्ट करें और अपने सच्चे कालिंग से समर्थन करें। संगतता और गतिविधियों को समझ कर अपने संबंधों में सुधार करें।अपना आदर्श करियर पथ खोजें और अपने व्यावसायिक जीवन के बारे में सूचित निर्णय लें। अपने जीवन में प्रभाव और ऊर्जाओं को समझकर सूचित निर्णय लें। अवरोधों की पहचान करें और इन्हें सफलतापूर्वक पार करने का तरीका सीखें। इस सफर में मेरे साथ शामिल हों

अपनी जीवन रेखा संख्या से गहरी स्पष्टता और दिशा प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। चाहे आप व्यक्तिगत विकास, संबंधों की अंतर्दृष्टि, या करियर मार्गदर्शन की तलाश में हों, न्यूमेरोलॉजी आपके रास्ते को प्रकाशित कर सकती है। मेरे साथ इन रहस्यमय संख्याओं का अन्वेषण करें और अपने भाग्य के रहस्यों को खोलें !अपनी व्यक्तिगत न्यूमेरोलॉजी रीडिंग के लिए आज ही संपर्क करें। चलो इस सफर पर साथ चलें और संख्याओं के जादू को खोजें !

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023